जीवन दर्शन

दैनिक ग्लोबल हेराल्ड

LOCAL TO GLOBAL

महानगर संस्करण

www.globalherald.news

शुक्रवार 28 मार्च, 2025 ■ वर्ष 14 ■ अंक 45 ■ इंदौर-भोपाल से प्रकाशित ■ पेज 8 ■ मूल्य रु 2.00

मैंने यही सीखा है कि चाहे जो कुछ भी हो, या आज वक्त चाहे कितना भी बुरा लगता है, लेकिन जीवन हमेसा आगे बढ़ता है, और यह कल बेहतर होगा - माया एंजेलो

पैसेंजर्स की परवाह करने का दावा करने वाली एयरलाइन में...

पृष्ठ 8 पर

न्यूज ब्रीफ

सड़क या छत पर नमाज पढ़ने पर होगी कार्रवाई, नमाज से पहले प्रशासन मुस्तैद

संभल। उत्तर प्रदेश के संभल में अलविदा की नमाज और ईद को देखते हुए प्रशासन विशेष मुस्तैद नजर आ रहा है। अलविदा की नमाज को लेकर प्रशासन ने साफ कहा है कि सिर्फ मस्ज़िदों में ही नमाज पढ़ी जा सकती है। संभल प्रशासन ने कहा है कि किसी को भी सड़कों पर या छतों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संभल के एएसपी श्रीश चंद्र ने गुरुवार को कहा कि पारंपरिक ढंग से नमाज अदा करने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन दुर्घटनाएं रोकने के लिए छतों पर बड़ी संख्या में एकत्रित होने पर रोक लगाई गई है। अलविदा की नमाज को लेकर एएसपी ने कहा कि लोग शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा करें, यह सुनिश्चित करने के लिए सेक्टर और जोन के अंतर्गत पर्याप्त संख्या में बल तैनात किया गया है।

अमेरिका-यूरोप में टेस्ला कार जला रहे, भारत लाने की तैयारी:2025 में मस्क को

वॉशिंगटन। बिजनेसमैन इलॉन मस्क की नीतियों से नाराज अमेरिका और यूरोप के लोग उनकी इलेक्ट्रिक कार टेस्ला को जला रहे हैं। पिछले बीते चार महीने में 100 से ज्यादा टेस्ला कारों में आगजनी या तोड़फोड़ की गई। यह सब घटनाएं ऐसे समय पर हो रही हैं, जब जल्द ही टेस्ला के इंडियन मार्केट में एंट्री की खबरें हैं। अमेरिका और यूरोप में टेस्ला कारों में आगजनी से मस्क और उनकी कंपनी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकारी कर्मचारियों की छंटनी से मस्क के खिलाफ नाराजगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इलॉन मस्क को सरकारी विभाग में सुधार के लिए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का प्रमुख बनाया है।

10 रु. के लिए 40 बच्चों ने हाथ काटे, डेयर गेम' खेल रहे थे 5 वीं-7 वीं के स्टूडेंट्स

अमरेली। गुजरात में एक गांव के सरकारी स्कूल में 40 बच्चों ने शार्पनर से अपने हाथ काट लिए। यह सभी 5वीं से 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं। पुलिस के अनुसार, यह एक 'डेयर गेम' था, जिसमें छात्र एक-दूसरे को चुनौती दे रहे थे कि यदि वे खुद को ब्लेड से घायल नहीं करेंगे तो उन्हें 10 रुपए देने होंगे। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए इन बच्चों ने अपने हाथों पर चोटें पहुंचाईं। बच्चों के हाथ में कट देखकर उसके पेरेंट्स ने स्कूल में जाकर इसकी शिकायत की, तब मामला उजागर हुआ इस बारे में एएसपी जयवीर गढ़वी ने बताया कि मोटा मुंजियासर प्राथमिक विद्यालय में कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं। जिसमें करीब छात्रों ने ब्लेड से अपने हाथ काट लिए हैं।

लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पास:शाह बोले- भारत धर्मशाला नहीं, बांग्लादेशियों से सख्ती से निपटेंगे

नई दिल्ली ■

लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास हो गया। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की घुसपैठ हो रही है। ऐसे में जो लोग भारत की व्यवस्था में योगदान करने, व्यापार और शिक्षा के लिए आते हैं, ऐसे सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन चाहे रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी अगर यहां अशांति फैलाने के लिए आते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ बड़ी कठोरता के साथ व्यवहार होगा। अगर कोई भारत को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता के साथ आता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा।'

उन्होंने कहा, 'मोदी सरकार केवल उन लोगों को भारत आने से रोकेगी जिनके इरादे गलत हैं। यह देश कोई धर्मशाला नहीं है। भारत में आने वाले सभी विदेशी नागरिकों की जानकारी रखी जाएगी। वे किस रास्ते से आ रहे हैं। कहां रुक रहे हैं। क्या कर रहे हैं। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल लोकसभा में 11 मार्च को पेश किया गया था। इस पर सत्ता और विपक्ष के 30 सांसदों ने अपनी बात रखी।

नियम बनाकर अवैध घुसपैठियों को रोक रहे

हमारी सीमा पर कुछ संवेदनशील स्थान हैं, सेना के अड्डे हैं, उनको दुनियाभर के लिए खुले नहीं छोड़ सकते थे। पहले भी घुसपैठियों को रोका जाता था, लेकिन तब इसका नियम नहीं था। हममें हिम्मत है नियम बनाकर रोकने की। पूरी व्यवस्था को वैज्ञानिक तरीके से एक कानून में बांधने का काम किया गया है।

भारत धर्मशाला नहीं है

'सरकार उन लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार है जो टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस या बिजनेस के लिए भारत आना चाहते हैं। मोदी सरकार केवल उन लोगों को भारत आने से रोकेगी जिनके इरादे गलत हैं। जो हमारे लिए खतरा पैदा करेंगे उनसे गंभीरता से निपटा जाएगा। यह देश कोई धर्मशाला नहीं है।'

भारत आए विदेशियों की जानकारी पुख्ता होगी

सुरक्षा की दृष्टि से ड्रग्स कार्टल, घुसपैठियों की कार्टल, हवाला व्यापारियों को समाप्त करने की व्यवस्था हम इस बिल में कर रहे हैं। पासपोर्ट एक्ट में पासपोर्ट-वीजा अनिवार्य होगा। विदेशियों के रजिस्ट्रेशन को और पुख्ता किया जाएगा।

विदेशी यात्रियों की सुविधा के लिए चौकियां बढ़ाई

विदेशी यात्रियों की सुविधा के लिए हमने 73% अप्रवासन चौकियां बढ़ाई हैं। 2024 में आठ करोड़ 12 लाख आवाजाही हुई है। फास्टैग अप्रवासन यात्री कार्यक्रम हमने आठ एयरपोर्ट पर लागू किया है, जिसमें यात्रियों की जांच में 30 सेकंड समय लगेगा।

फेंसिंग के लिए ममताजी नहीं दे रहीं जमीन

पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की घुसपैठ हो रही है। 450 किमी आपकी कृपा से खुली सीमा है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, आधार कार्ड बनते हैं और देशभर में फैल जाते हैं। जितने घुसपैठिए पकड़े गए हैं, सबके पास 24 परगना के आधार कार्ड मिले हैं। 'जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर हुड़दंग करता है,

कठुआ एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर, 3 जवान शहीद जवानों को पेट में गोली लगी थी

जम्मू ■

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों और आर्तकियों के बीच मुठभेड़ में गुरुवार को तीन जवान शहीद हो गए। जवानों ने 3 आतंकी मार गिराए। सुबह से जारी मुठभेड़ में डीएसपी धीरज सिंह समेत पांच सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे। इनमें से तीन की इलाज के दौरान मौत हो गई। तीन शहीद जवानों के नाम तारिक अहमद, जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह हैं।

इन्हें जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। जम्मू-कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के इन जवानों को पेट में गोली लगी थी। एनकाउंटर राजबाग के घटी जुठाना इलाके के जखोले गांव के पास चल रहा है। यहां करीब 9

आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। एसओजी, सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ की जॉइंट टीम ने तीन आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षाबलों ने आतंकियों की धरपकड़ के लिए थर्मल इमेजिंग, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, बुलेटप्रूफ वाहन और खोजी कुत्तों की मदद से बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

सरकार ने हाईकोर्ट में पेश की सफल ट्रायल रन रिपोर्ट

यूनियन कार्बाइड: अब 72 दिन में जलाया जाएगा पूरा कचरा

जबलपुर ■

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में गुरुवार को पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निष्पादन के ट्रायल रन को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार ने बताया कि तीन ट्रायल रन की रिपोर्ट सही आई है।

अब तक करीब 270 किलो प्रति घंटे की दर से कचरा जलाया गया, जिसका ट्रायल रन सफल रहा। सरकार ने कहा कि इसी स्पीड से कचरे को जलाकर अगले 72 दिन में समाप्त किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 72 दिनों में जहरीला कचरा जलाकर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। वहीं गैस पीड़ित संगठनों ने कोर्ट को बताया कि जलाने की प्रक्रिया सही इसलिए नही है, क्योंकि 300 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को जलाने के बाद समस्या तीन गुना बड़ी हो जाएगी। सरकार ने खुद ही बताया है कि 300 मीट्रिक टन कचरा जलाने पर 900 मीट्रिक टन जहरीली राख को फिर से पीथमपुर की प्लास्टिक जमीन में डाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से प्रदूषण होगा ही। जहरीला कचरा जलाने के मामले में नियमों का पूरी तरह से पालन हो इसके लिए हाईकोर्ट ने सरकार का आगाह किया है।

दो हजार बहनों के सामूहिक विवाह में शामिल होना अदभुत अनुभव: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल ■

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि झाबुआ में एक साथ लगभग दो हजार जोड़ों के सामूहिक विवाह में शामिल होने का आनंद अदभुत और अविस्मरणीय है। उन्होंने नव-विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए सभी के मंगलमय और सुखद दांपत्य जीवन की कामना की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मनुष्य जीवन के 16 संस्कारों में से पाणिग्रहण संस्कार गृहस्थ जीवन में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण संस्कार है। इसमें 7 फेरों से 7 वचनों को पूरा कर सात जन्मों तक बंधन में बंधते हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह/निकाह सम्मेलन में शामिल जोड़ों को विवाह और निकाह की बधाई देते हुए सभी के जीवन में खुशियों की कामना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव इंदौर संभाग के झाबुआ में सामुहिक विवाह समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्मेलन में 11 जोड़ों को प्रतीकात्मक रूप से 49-49 हजार की राशि के चेक भी प्रदान किये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने झाबुआ जिले के निवासियों को सौगात देते हुए कहा कि राणापुर क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या के निराकरण के लिए भांडाखेड़ा बैराज, नागन खेड़ी, गलती, छायण, झालरवा, बुदाशाला और कल्लीपुरा में बैराज बनाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबद्ध झाबुआ में मेडिकल कॉलेज भी बनाया जायेगा। झाबुआ के विकास के लिये सभी कार्य किये जायेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के विकास में सभी वर्गों का विकास समाहित है। किसी भी वर्ग को विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहने दिया जायेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुरूप सबका साथ लेकर सबका विकास किया जायेगा, जिसमें सबके प्रयास और सबका विश्वास शामिल रहेगा।

महिला बलात्कार नहीं कर सकती लेकिन रेप के लिए उकसा सकती है: हाईकोर्ट का फैसला

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल ने बलात्कार के मामले में भारतीय कानून के तहत उकसावे की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा कि भले ही कोई महिला स्वयं बलात्कार के लिए आरोपित नहीं हो सकती लेकिन वह आईपीसी की धारा 109 के तहत बलात्कार के लिए उकसाने की दोषी हो सकती है। रेप के लिए उकसाने वाली आरोपी महिला के खिलाफ भी 376 १/६ 34, 109 और 506-11 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जज कैश केस-सुको में सुनवाई आज, एफआईआर की मांग

नई दिल्ली ■

दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के बंगले पर कैश मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिका में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका एडवोकेट मैथ्यूज जे नेदुम्परा ने दायर की है। सुप्रीम कोर्ट कॉज लिस्ट के मुताबिक मामले की सुनवाई जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच सुनवाई करेगी।

याचिका में 34 साल पुराने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को भी चुनौती दी गई है। 1991 में के वीरस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि मुख्य न्यायाधीश की परमिशन के बिना हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस शुरू नहीं किया जा सकता। दरअसल, जस्टिस वर्मा के घर में 14 मार्च को होली के दिन आग लग गई थी। फायर सर्विस की टीम जब उसे बुझाने गई तो स्टोर रूम में उन्हें बोरियों में भरे 500-500 रुपए के अधजले नोट मिले थे। तभी से यह पूरा मामला सुर्खियों में बना हुआ है।

शार्दूल-पूरन के प्रदर्शन से जीता लखनऊ हैदराबाद टीम को 5 विकेट से हराया

हैदराबाद ■

लखनऊ सुपरजायंट्स ने आईपीएल-2025 में पहली जीत दर्ज की। टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। राजीव गांधी स्टेडियम की बैटिंग पिच पर एलएसजी से शार्दूल ठाकुर ने 4 विकेट लिए।

वहीं निकोलस पूरन ने 26 गेंद पर 70 रन बनाए। गुरुवार को हैदराबाद में एलएसजी ने बॉलिंग चुनी। एसआरएच ने 9 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ट्रैविस हेड ने 47 और अनिकेत वर्मा ने 36 रन बनाए। लखनऊ ने 16.1 ओवर में 5 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने 52 रन बनाए। हैदराबाद से पैट कमिंस ने 2 विकेट लिए। बैटिंग पिच पर नई गेंद से बॉलिंग करने उतरे शार्दूल ठाकुर ने पावरप्ले में 2 विकेट लिए। उन्होंने डेथ ओवर्स में रन नहीं खर्च किए और हैदराबाद के बैटर्स पर दबाव बनाया। उन्होंने महज 34 रन दिए और 4 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, अभिनव मनोहर और मोहम्मद शमी उनकी गेंदों पर आउट हुए।

ओडिशा में कांग्रेस कार्यकताओं और पुलिस की झड़प, लाठियां बरसाई, वाटर कैनन चलाई

भुवनेश्वर ■

ओडिशा विधानसभा का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस नेताओं पर गुरुवार को पुलिस ने लाठियां बरसाईं और वाटर कैनन चलाईं। दर्जनों कार्यकर्ता घायल हो गए। कांग्रेस 14 विधायक के निलंबन का विरोध कर रही थी। दरअसल 25 मार्च को कांग्रेस के 12 विधायक निलंबित कर दिए गए थे। इसके बावजूद विधायक प्रदर्शन करते रहे और पूरी रात सदन में बिताई। विधानसभा के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते रहे।

अगले दिन यानी 26 मार्च को कांग्रेस कार्यकर्ता और निलंबित विधायक विधानसभा के बाहर

प्रदर्शन करते रहे। वे विधानसभा की बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद जमकर धक्का-मुक्की हुई। सदन के भीतर कांग्रेस के बचे हुए दो विधायकों तारा प्रसाद बाहिनीपति और रमेश जेना ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया। दोनों सदन की वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे थे इसलिए उन्हें भी निलंबित कर दिया गया था।

व्यंग्य : दुष्कर्मियों को बचाने जैसे फैसले पर सुप्रीम रोक..?

ग्लोबल हेराल्ड
न्यूज एनालिसिस
GHNA
दिलीप शर्मा
(वरिष्ठ पत्रकार)

न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले दो मामले खबरों की सुर्खियों में रहे हैं. पहला दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में करोड़ों केस मिलने की जांच सुप्रीम कोर्ट कर रहा है. इधर सुप्रीम कोर्ट के जज गवई व मसीह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज मिश्रा के फैसले पर रोक लगाकर कड़ी निंदा की है और फैसले को अमानवीय, असंवेदनशील बताकर निंदा की. क्यों ऐसा कहा यह जानकर भी लोग चौंक जाएंगे कि एक जज का ये कैसा फैसला था..?

ब्रेस्ट पकड़ना दुष्कर्म नहीं : ऐसे फैसले को अमानवीय बताया सुप्रीम जज गवई व मसीह ने..!

नाबालिग लड़की के साथ रेप की कोशिश से जुड़े एक मामले में आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के विवादित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. जस्टिस बी आर गवई एवं आगस्टीन जार्ज मसीह ने फैसले को असंवेदनशील एवं अमानवीय कहा. सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह सुनवाई शुरू की. कोर्ट ने मामले से जुड़े पक्षों, यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है.17 मार्च को आए इस फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज श्री मिश्रा ने कहा था कि पीड़िता को खींच कर पुलिया के नीचे ले जाना, उसके ब्रेस्ट को पकड़ना और पजामे के डोरी को तोड़ना रेप की कोशिश नहीं कहलाएगा. 11 साल की लड़की के साथ हुई इस घटना के बारे में हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा का निष्कर्ष था कि यह महिला की गरिमा पर आघात का मामला है. इसे रेप या रेप का प्रयास नहीं कह सकते.जस्टिस मिश्रा ने मामले में 2 आरोपियों पर लगी आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 18 (अपराध की कोशिश) और पॉक्सो एक्ट की धारा हटा दी थी. उन्होंने 354-इ (महिला को निर्वस्त्र करने के मकसद से बलप्रयोग) और पॉक्सो एक्ट की धारा 9 (गंभीर यौन हमला) के तहत मुकदमा चलाने को कहा था. हाई कोर्ट जज के निष्कर्ष और उनकी टिप्पणियों के दूरगामी असर को देखते हुए लोग सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान की मांग कर रहे थे. 'वी द वीमेन' नाम की संस्था ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी थी. इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनवाई शुरू की है.सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि इस मामले में फैसला अचानक नहीं आया था. हाई कोर्ट जज ने 4 महीना सुरक्षित रखने के बाद फैसला दिया. यानी पूरे विचार के बाद फैसला दिया गया है. फैसले में कहीं गई कई बातें कानून की दृष्टि से गलत और अमानवीय लगती हैं. ऐसे में हम इस फैसले पर रोक लगा रहे हैं और सभी पक्षों को नोटिस जारी कर रहे हैं.सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब हाई कोर्ट जज ने 4 माह का समय लिया तो क्या यह सोचा कि आरोपियों को कैसे बचाना है..क्या संदिग्ध नहीं लगता..?

भावना हत्याकांड के तीनों आरोपी गिरफ्तार, मुकुल से चली थी गोली

इंदौर ■

इंदौर में हुए भावना हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस हत्याकांड के आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने इन पर 10-10 हजार का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने आरोपी आशु यादव,मुकुल और स्वास्तिका को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है, ताकि वे विदेश न भाग सके।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भावना को मुकुल के हाथ से चली गोली लगी थी। जो उसकी मौत की वजह बनी। पुलिस ने

आरोपियों को दतिया से पकड़ा है। आरोपी इंदौर में भावना को बांबे अस्पताल में भर्ती कराने के बाद भाग गए थे। पुलिस के अनुसार आरोपी बस में बैठकर इंदौर से भोपाल गए। वहां पर विख्यात पाठक के घर पर रुके थे। इस वजह से उसे भी केस में आरोपी बनाया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी भोपाल से दतिया गए। अफसरों ने ग्वालियर और दतिया में उनके परिजनों से भी पूछताछ की, लेकिन आरोपियों ने अपने परिजनों से भी संपर्क नहीं किया है। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में विख्यात पाठक ने रेंट एग्रीमेंट कराया था। वह आशु का दोस्त है।

न्यूज ब्रीफ

चमेलीदेवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सिट्रोनिक्स में भी लगी इंदौर पुलिस की साइबर पाठशाला

इंदौर (ग्लोबल हेराल्ड)। वर्तमान में बढ़ते सायबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिये, इसके प्रति लोगों में जनजागरूकता लाने हेतु, पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सायबर जागरूकता हेतु लगातार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी अनुक्रम में आज दिनांक 27.03.25 को अति. पुलिस उपायुक्त क्राइम इंदौर श्री राजेश दंडोतिया टीम के साथ चमेलीदेवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा आयोजित सिट्रोनिक्स कार्यक्रम में पहुँचकर करीब 500 स्टूडेंट्स को विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड और सोशल मीडिया से संबंधित अपराधों की जानकारी दी और सायबर अपराध होने पर सायबर हेल्पलाइन-1930, पोर्टल www.cybercrime.gov.in या इंदौर पुलिस की सायबर हेल्पलाइन 7049124445 आदि पर किस प्रकार शिकायत करें और सायबर अपराधों से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखें आदि के संबंध में बताया। चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स इंदौर द्वारा हर साल सिट्रोनिक्स का आयोजन किया जाता है, और जो 27 से 29 तारीख तक चलेगा जिसका शुभारंभ आज किया गया। इस वर्ष सिट्रोनिक्स की थीम सायबर सिक्योरिटी है जिसके तहत इंदौर पुलिस द्वारा साइबर पाठशाला लगाकर, स्टूडेंट्स को साइबर अपराधों के प्रति जागरुक किया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने सभी को सायबर अवेयरनेस के पम्पलेट्स व स्टिकर्स भी दिए और सभी को साइबर जागरूकता लाने में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया।

संपत्तियों के पंजीयन के लिये अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे पंजीयन कार्यालय

इंदौर (ग्लोबल हेराल्ड)। नये वित्तीय वर्ष में सम्पत्तियों की बढने वाली गाईड लाईन को देखते हुए आमजन द्वारा पंजीयन कार्यालयों में अपने संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर दिनांक 29, 30 एवं 31 मार्च 2025 को छुट्टी के दिन भी पंजीयन कार्यालय खुले रखकर इन्दौर पंजीयन विभाग ₹पंजीयन महोत्सव' मनाने की तैयारी में है। वरिष्ठ जिला पंजीयक डॉ. अमरेश नायडू ने बताया है कि बढ़ी हुई गाईड लाईन 01 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, इसके पूर्व आमजन चाहेंगे कि, उनकी संपत्तियों की रजिस्ट्री 31 मार्च 2025 तक हो जाये। ₹पंजीयन महोत्सव की तैयारी हेतु आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुये सभी पंजीयन कार्यालय में छाया हेतु टेंट, कुर्सी, पीने के पानी, कूलर/ए.सी. तथा अन्य सुविधाओं के इंतजाम किये जा रहे है। इस संबध में आमजन से अपील की गई है कि, वे अपने दस्तावेजों का पंजीयन कार्यालय में प्रातः 10 बजे से शाम 7 बजे तक करा सकते है। आमजन को पर्याप्त सुविधा प्रदान करने हेतु इन्दौर पंजीयन विभाग तत्पर है। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर मोबाइल नम्बर 7999309796 पर संपर्क कर सकते है।

इंदौर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान प्रतिमा की स्थापना की तैयारी, स्थल का निरीक्षण

इंदौर (ग्लोबल हेराल्ड)। निरंजनपुर चौराहे पर स्थल का निरीक्षण, राजपूत समाज के पदाधिकारी रहे मौजूद, इंदौर के निरंजनपुर चौराहे पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा स्थापना की तैयारी शुरू हो गई है। प्रतिमा स्थल और सौन्दर्यीकरण कार्य के लिए एम. आई. सी. सदस्य राजेंद्र राठौड़ ने आई. डी. ए. अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रतिमा निर्माण समिति के अध्यक्ष मुकेश चौहान और पूर्व नगर निगम सभापति अजयसिंह नरूका भी मौजूद रहे। राजपूत समाज के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखें। कार्यक्रम में राजपूत समाज चेतना मंडल के संयोजक रतन सिंह राजपूत, अखिल भारतीय युवा क्षत्रिय महासभा इंदौर के अध्यक्ष पप्पू ठाकुर, रजत सिंह भदौरिया, भगवान सिंह बुंदेला, जाहर सिंह पवार, अंकित चौधरी और समाज के वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे।

दस्तावेजों के पंजीयन की अधिक संख्या को देखते हुए पंजीयन की विशेष व्यवस्था

इंदौर (ग्लोबल हेराल्ड)। मार्च माह के अंतिम दिनों में दस्तावेजों का पंजीयन अधिक संख्या में होता है। इस वर्ष भी मार्च के आगामी दिनों में सामान्य दिवसों की अपेक्षा दस्तावेजों के पंजीयन में वृद्धि होने की संभावना है। इस हेतु सम्पदा 1.0 में शाम 7:00 बजे तक स्लॉट ओपन किये गये है। प्रति उप पंजीयक 86 स्लॉट उपलब्ध है। सम्पदा 2.0 में भी पर्याप्त संख्या में स्लॉट उपलब्ध है। वरिष्ठ जिला पंजीयक श्री दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि इसको देखते हुए जिले के समस्त ई-पंजीयन सेवा प्रदाताओं को आवश्यक व्यवस्था करने को कहा गया है। कहा गया है कि सम्पदा खाते एवं वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस पहले से लेवें और उसे मेंटेन करें ताकि अंतिम समय पर क्रेडिट लिमिट नहीं बनने या लिमिट अटकने पर परेशानी से बचा जा सके। कार्य के अनुमान के अनुसार बैंक खाते में पर्याप्त बैलेस रखे ताकि अंतिम समय में दस्तावेजों के पंजीयन के लिये क्रेडिट लिमिट बनाई जा सके। किये जाने वाले कार्य की क्षमता के अनुसार ही पक्षकारों को कार्यालय में बुलाए। सुव्यवस्थित ढंग से प्लानिंग के अनुसार कार्य करें ताकि गर्मी के समय में पक्षकार को अनावश्यक कठिनाई / परेशानी ना हो। पीने के पानी, टॉयलेट इत्यादि की व्यवस्था रहे। पक्षकारों को बुक किए गए स्लॉट के सही समय पर उप पंजीयक कार्यालय में भेजे ताकि उप पंजीयक कार्यालय में उनका काम सुगमता से हो सके। सुबह के स्लॉट का उपयोग करें और सुबह के स्लॉट के पक्षकारों को सुबह ही उप पंजीयक कार्यालय में भेजे।

नवाचार के तहत इंदौर में उपभोक्ताओं के लिये राशन भी पोषण भी

इन दुकानों से राशन के साथ पोषण संबंधी मोटा अनाज, दाले, सब्जियां, दूध, पनीर, मसाले भी मिलेगें

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

इंदौर जिले में उपभोक्ताओं के हित में और उचित मूल्य दुकानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए शासन-प्रशासन द्वारा नवाचार किया जा रहा है। कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकानों की सूरत और सीरत बदलने लगी है। अब शासकीय उचित मूल्य दुकानों से उपभोक्ताओं को राशन के साथ ही गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पाद और अन्य पोषण सामग्रियाँ भी उचित मूल्य पर देने की व्यवस्था शुरू की गई हैं। इन दुकानों से जैविक उत्पाद भी उपलब्ध कराये जाने के लिए आज उचित मूल्य दुकान आदर्श महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार बाणगंगा इंदौर पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित कर जनपोषण केन्द्र का औपचारिक विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में वीडियों कांफ्रेंस के माध्यम से भारत सरकार खाद्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री रविशंकर, ज्वाईंट डायरेक्टर एनएफएसए भारत सरकार श्री जय पाटील, प्रदेश के आयुक्त खाद्य श्री कर्मवीर शर्मा वर्चुअली सम्मिलित हुए। कंसल्टेंट श्री अभिषेक कुमार,श्री चंद्रपाल यादव , मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सिद्धार्थ जैन, जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एम.एल. मारु, पायलट प्रोजेक्ट के 30 दुकानों के डीलर, स्थानीय पार्षद श्रीमती संध्या जायसवाल, हितग्राही उपभोक्ता कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।

शुभारंभ में संयुक्त सचिव भारत सरकार श्री रविशंकर द्वारा जनपोषण केन्द्र के पायलट प्रोजेक्ट के बारे में डीलर को आवश्यक मार्गदर्शन निर्देश दिए गये। उपभोक्ताओं को पोषण संबंधी वस्तुएं दुकान के माध्यम से सहज गुणवत्तायुक्त सामग्री उपलब्ध हो सके तथा उचित मूल्य दुकान को आर्थिक रूप से सुदृढ एवं बहुउददेशीय बनाने के महत्व को विस्तार से बताया। आयुक्त खाद्य द्वारा भारत सरकार के पायलट प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने तथा उपभोक्ताओं को पोषण संबंधित जरूरते इन केन्द्रों के माध्यम से पूरी हो सके इसके लिए डीलर खाद्य विभाग की टीम को इसके संचालन निरंतर करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया। बताया गया कि सरकारी राशन की दुकानों को पोषण केंद्रों में बदलने की यह एक अभिनव पहल है। इसका मकसद, लोगों को पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ मुहैया कराना है। उपभोक्ता भंडार के विक्रेता द्वारा पोषण संबंधी विशेष तौर पर उचित दर एवं क्वालिटी के साथ दी जाने का प्रयास किया जाता है। कार्यक्रम में जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एम.एल. मारु द्वारा इन दुकानों पर किए गए नवाचार के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि इंदौर में 30 जन पोषण केन्द्र स्थापित किये गये है। इन जनपोषण केन्द्रों पर मोटा अनाज, दाले, हरी सब्जियां, दूध ,दही, पनीर, गिर गाय का शुद्ध घी,मसाले, स्वसहायता समूह की इंदौर की बहनों द्वारा बनाए गए अचार,पापड मसाले इत्यादि उत्पाद बिक्री हेतु उपलब्ध है। जनपोषण केन्द्र पर होम डिलेवरी के माध्यम से भी मोटा अनाज सामग्री आदि प्रदाय करने के संबंध में की गई पहल, नवाचार के संबंध में बताया गया।

उपभोक्ताओं ने भी की सराहना

जनपोषण केन्द्र के शुभारंभ उपरांत लगभग 50 से ज्यादा उपभोक्ताओं ने मोटा अनाज,दाले,दूध ,दही, घी, मसाले आदि क्रय किए। स्थानीय उपभोक्ताओं द्वारा उचित मूल्य दुकान पर उक्त सामग्री की उपलब्धता पर प्रसन्नता जाहिर की एवं राशन के साथ अन्य सामग्री भी क्रय करने अन्यत्र नहीं जाना पडेगा कि सुविधा शासन द्वारा दिए जाने पर आभार व्यक्त किया। उचित मूल्य की दुकानों पर जन पोषण केन्द्र शुरू हो जाने के बाद उपभोक्ताओं को तो लाभ होगा ही, इसके साथ ही राशन डीलरों की आय में भी वृद्धि होगी और लोगों को पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलेंगे। जन पोषण केंद्रों में पोषण से जुड़े उत्पादों का भंडारण होगा। इन केंद्रों में राशन डीलरों को आय का एक और जरिया मिल सकेगा। इन केंद्रों में राशन डीलरों को आसान लोन की सुविधा भी मिलेगी। इन केंद्रों में डिजिटल टूल्स और सहायता प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाएगा तथा कॉमन सर्विस सेंटर, बैंकिंग कोरसपोंडेंस बनाने की कार्यवाही भी जनपोषण केन्द्र पर की जा रही है। कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए भारत सरकार के संयुक्त संचालक खाद्य श्री रविशंकर ने राज्य के प्रथम जन पोषण केन्द्र प्रारंभ करने पर शुभकामनाये एवं बधाई दी।

1 अप्रैल से जमीन की सरकारी कीमतों में भारी इजाफा, 4972 स्थानों पर बढ़ेगी स्टाम्प ड्यूटी

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

1 अप्रैल से लागू होने वाली नई गाइडलाइन के तहत स्टाम्प ड्यूटी में 10 प्रतिशत से लेकर 274 प्रतिशत तक की भारी बढ़ोतरी की जा रही है। इससे जुड़े सभी प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी के लिए आज भोपाल मुख्यालय भेजा जाएगा। पंजीयन विभाग ने इस प्रस्तावित गाइडलाइन पर प्राप्त 138 दावे-आपत्तियों का समाधान कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप 70 नई कॉलोनियों को शामिल किया गया है, साथ ही कई गांवों की गाइडलाइन दरों में भी इजाफा किया गया है। अब कुल मिलाकर 4972 स्थानों पर सरकारी जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी और इन्हीं के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी वसूली की जाएगी।

जनप्रतिनिधियों और किसानों की मांग पर बढ़ी दरें

वरिष्ठ जिला पंजीयक अमरेश नायडू के अनुसार, काली बिल्लौद के किसानों ने मांग की थी कि 2016 से गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई है, इसलिए उनकी बात को मान्य किया गया। इसी तरह विधायक मधु वर्मा द्वारा तिल्लौर बुजुर्ग की गाइडलाइन बढ़ाने की अनुशंसा की गई, जिसे स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं, जीतू पटवारी और मुकेश पटवारी ने कैलोदकर्तान और वतनखेड़ी गांवों की गाइडलाइन बढ़ाने की मांग की थी, जिसे आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है। प्राप्त प्रस्तावों में कुछ अन्य गांवों के साथ-साथ 70 नई कॉलोनियों को भी गाइडलाइन में सम्मिलित करने का सुझाव था, जिसे मंजूरी दे दी गई है। इसके परिणामस्वरूप अब कुल 310 नई कॉलोनियां गाइडलाइन में शामिल हो चुकी हैं। इस प्रकार 1 अप्रैल से कुल 4972 स्थानों पर जमीन की सरकारी कीमतों में वृद्धि प्रभावी होगी। इसके आधार पर स्टाम्प ड्यूटी का निर्धारण किया जाएगा, जिससे शासन को राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।

इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर और अन्य परियोजनाएं शामिल

गाइडलाइन में प्राधिकरण की प्रस्तावित टीपीएस योजनाओं में शामिल जमीनों के अलावा इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर तथा अन्य प्रमुख परियोजनाओं से जुड़ी जमीनों को भी शामिल किया गया है। स्टाम्प ड्यूटी से शासन को सबसे अधिक राजस्व इंदौर से प्राप्त होता है। चालू वित्त वर्ष में शासन ने 3200 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से अब तक लगभग 2300 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। शेष सप्ताह में अधिक से अधिक रजिस्ट्रियों की संभावना है, जिसके चलते अंतिम 3-4 दिनों में स्लॉटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

मोदी के सामने स्पीच देने जा रही है इंदौर की होनहार बेटी

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

मध्यप्रदेश की तीन मेधावी लड़कियां संसद के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने स्पीच देने का अवसर प्राप्त करेंगी। इनका चयन राज्य स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता में हुआ है, जिसे विधानसभा के मानसरोवर सभागार में आयोजित किया गया था। यह प्रतियोगिता 'विकसित भारत' थीम पर आधारित थी, जिसमें प्रदेशभर के युवा शामिल हुए थे। प्रतियोगिता में इंदौर की सजल जैन, भिंड की यति सिंह सिसोदिया और राशि त्रिपाठी का चयन हुआ है, जिनको संसद में प्रधानमंत्री के समक्ष अपने विचार रखने का मौका मिलेगा।

राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली इंदौर की छात्रा सजल जैन ने अपने भाषण में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि अधिकार और कर्तव्य की यात्रा में वर्तमान समय में अधिकार कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, जबकि कर्तव्य पीछे रह गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता है ताकि समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। उनके विचारों ने सभी को यह एहसास दिलाया कि केवल अधिकारों की मांग नहीं, बल्कि कर्तव्यों का भी पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इस राज्य स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से कुल 200 युवा भागी थे। प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को भारतीय संविधान, उनके अधिकारों, कर्तव्यों और प्रगति के बारे में जागरूक करना था।

लाखों के कर्ज से परेशान वीडियोग्राफर ने फंदा लगाकर दे दी जान, इकलौता था

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

एक वीडियोग्राफर ने फंदा लगाकर जान दे दी। उस पर लाखों रुपये का कर्ज था और लोग उस पर कर्ज चुकाने का दबाव बना रहे थे। इससे वह तनाव में आ गया था। रात को उसने अपने घर पर फांसी लगा दी। वह परिवार में इकलौता था। द्वारकापुरी क्षेत्र में रहने वाले अमित पिता महेश चावड़ा ने अपने घर में फंदा लगा लिया। बुधवार रात को जब मां ने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो उसने नहीं खोला। माता-पिता एक रिश्तेदार के यहां खाने गए थे। अमित घर पर ही था। रात को जब वे लौटे तो घटना का पता चला। दरवाजा नहीं खोलने पर आस पड़ोसियों ने रोशनदान से झांककर देखा तो अमित फंदे पर लटका हुआ था।

इसके बाद परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने आकर दरवाजा खोला और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद कमरे की तलाशी ली। हालांकि, पुलिस को कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। परिजनों ने बताया कि उसने फोटोग्राफी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर्ज लिया था, लेकिन वह चुका नहीं पा रहा था। इस कारण वह तनाव में रहता था। अमित माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके इस कदम से माता-पिता सदमे में है। परिजनों ने बताया कि अमित ने नए कैमरे और उपकरण कर्ज लेकर खरीदे थे। उसे काम भी मिलता था, लेकिन लोग पैसा उधार कर लेते थे और समय पर नहीं देते थे। इस कारण वह कर्ज नहीं उतार पा रहा था। इसे लेकर अक्सर वह तनाव में रहता था। पुलिस ने अमित का मोबाइल भी जब्त किया है।

मॉल में धोती पहनने पर विवाद... युवाओं ने किया विरोध प्रदर्शन

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

इंदौर के एक मॉल में धोती पहनने पर विवाद हुआ और बाद में बड़ी संख्या में युवा मॉल में पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ये सभी युवा धोती पहने हुए थे और इन्होंने भारतीय परिधान पहनने के पक्ष में नारे भी लगाए।

क्या है मामला

देवास के विजय सिंह ठाकुर नाम के जिम संचालक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि इंदौर के एक मॉल में वह धोती पहनकर गए तो वहां के सुरक्षाकर्मियों ने उनसे विवाद किया। इसके बाद जब यह वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर भारतीय परिधानों के प्रति लोगों की भावनाएं उमड़ गईं। रविवार को विजय सिंह ठाकुर अपने दोस्तों के साथ मॉल गए थे। उन्होंने उस समय हुए विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसके बाद कल बुधवार को फिर वे अपने दोस्तों के साथ मॉल में गए और धोती पहनकर पूरे मॉल में घूमे। उस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में युवा थे जो सभी धोती पहने हुए थे। सभी ने सोशल मीडिया के लिए खूब रील्स बनाई और कहा कि भारतीय परिधानों पर हम सभी को गर्व होना चाहिए।

दस लाख से अधिक लोगों ने देखा

विजय सिंह ठाकुर का यह वीडियो दस लाख से अधिक लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा है, कई लोगों ने शेयर किया है। विजय ने लिखा है कि हिन्दू हो तो यह वीडियो जरूर शेयर करो। इसे 70 हजार लोगों ने लाइक किया है। इस मामले में मॉल प्रबंधन से बातचीत करने के लिए कई बार फोन लगाया गया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। सोशल मीडिया पर भी मॉल प्रबंधन की तरफ से इस विवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

5वीं और 8वीं परीक्षाओं के परिणाम शुक्रवार 28 मार्च को होंगे घोषित

इंदौर। राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में आयोजित कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न परीक्षाओं का परिणाम, शुक्रवार 28 मार्च 2025 को दोपहर एक बजे घोषित किया जायेगा। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्री हरजिंदर सिंह ने बताया कि परिणाम शुक्रवार 28 मार्च को दोपहर एक बजे परीक्षा परिणाम पोर्टल पर जारी किया जायेगा। विद्यार्थी, अभिभावक एवं शिक्षकगण उक्त परिणामों को राज्य शिक्षा केन्द्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in/result.aspx पर अपना रोल नम्बर/समग्र आईडी प्रविष्ट कर देख सकते हैं। इसी पोर्टल पर शिक्षक, संस्था प्रमुख अपनी शाला का विद्यार्थीवार परिणाम भी देख सकेंगे। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र ने बताया कि उक्त परीक्षाओं का संचालन विगत 24 फरवरी से 5 मार्च, 2025 के मध्य किया गया था।

बदलें खुद को...

फिर भी जिंदगी हसीन है...
dreamsachieverspune@gmail.com

निर्मल भटनागर (एजुकेशनल कंसलटेंट एवं मोटिवेशनल स्पीकर)
ग्लोबल हेराल्ड

दोस्तों, इस दुनिया में जीवन को बेहतर बनाने के लिए आत्म परिवर्तन से बेहतर और कुछ नहीं है। चलिए इसी बात को हम एक कहानी से समझने का प्रयास करते हैं। कुछ सालों पहले की बात है, कुछ शिष्य समूह बनाकर अपने गुरु के पास पहुंचे और उनसे सलाह माँगते हुए बोले, 'गुरुजी हम सभी तीर्थयात्रा पर जा रहे हैं ताकि हम अपना मन शुद्ध और पवित्र कर, अपने जीवन को सुधार सकें। कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हम किन-किन स्थानों पर जाएं और वहाँ किस तरह पूजन आदि करें जिससे हमें अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके और हमारा जीवन सुधर सके।'

शिष्यों का प्रश्न सुन गुरु मुस्कुराए फिर बोले, 'वत्स! अगर तुम वाक़ई अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हो और इस तीर्थ यात्रा से अधिकतम लाभ लेकर अपने जीवन को सुधारना चाहते हो, तो सिर्फ़ एक कार्य करो, मेरा दिया करेला अपने साथ लेकर जाओ और फिर जहाँ भी जाओ इसे अपने साथ ले जाओ। जहाँ भी दर्शन करो, इसे भी दर्शन कराओ और जब यात्रा पूर्ण कर लो तो इस करेले के साथ सीधे मेरे पास आश्रम आ जाओ।' गुरु की सलाह सुन शिष्य थोड़े हैरान थे, पर अपने गुरु पर विश्वास होने के कारण कहीं ना कहीं संतुष्ट भी थे। उन्होंने गुरु की सलाह मानी और सबने गुरु से लिए करेले के साथ तीर्थ यात्रा प्रारंभ कर दी। अब वे जिस भी धार्मिक स्थल पर जा रहे थे, अपने साथ उस करेले को ले जा रहे थे। अर्थात् वे उस करेले को ले पहाड़ी की चोटियों पर गए, नदी किनारों और जंगलों में स्थित मंदिरों में गए और उसे अनेकों मंदिरों में पूजा में भी अपने साथ रखा। तीर्थयात्रा के अंतिम पड़ाव से वे सीधे गुरु के आश्रम आए और उनके दर्शन कर आशीर्वाद लिया। सामान्य बातचीत के बाद गुरु ने सभी शिष्यों से पूछा, 'आशा करता हूँ इस धार्मिक यात्रा से तुम सभी को आत्मिक शांति का अनुभव हुआ होगा।' प्रश्न सुनते ही सभी शिष्यों के चेहरे उतर गए और उन्होंने उनके प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। शिष्यों के चेहरे पर मायूसी देख गुरुजी बोले, 'चलो कोई बात नहीं, तूम जो अपने साथ करेले लेकर गए थे उन्हें इकट्ठा करो। आज संध्या के भोज में हम सब उन्ही करेलों की सब्जी खाएँगे।' सभी शिष्यों ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और रात के भोजन में करेले की सब्जी बनवाई। उस रात के भोज की शुरुआत गुरु ने करी और पहला निवाला खाते ही चेहरा बिगाड़ते हुए बोले, 'यह सब्जी तो एकदम कड़वी है। इस करेले के स्वाद में तो इतनी तीर्थयात्रा के बाद भी परिवर्तन नहीं आया। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ?' गुरु का प्रश्न सुनते ही एक शिष्य बोला, 'गुरुजी, करेला तो अपनी प्रकृति से ही कड़वा होता है। तीर्थ यात्रा से इसका स्वाद कैसे बदलेगा?' शिष्य का जवाब सुनते ही गुरु जी एकदम गंभीर हो गए और फिर बोले, 'वत्स! बिल्कुल सही कहा तुमने, करेला तो अपनी प्रकृति से ही कड़वा होता है और तीर्थ यात्रा से इसकी प्रकृति बदलने वाली नहीं है। यही बात मैं तुम सभी को समझाने का प्रयास कर रहा था। तीर्थयात्रा के रूप में अपना बाहरी वातावरण बदल लेने से तुम अपने मन को कड़वे या नकारात्मक विचारों से मुक्त नहीं कर सकते हो। जब तक तुम भीतर से खुद को नहीं बदलोगे, तब तक कोई भी बाहरी यात्रा तुम्हें सुख, शांति नहीं दे पाएगी। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने शुरुआत में क्यों कहा था कि 'इस दुनिया में जीवन को बेहतर बनाने के लिए आत्म परिवर्तन से बेहतर और कुछ नहीं है।' याद रखियेगा, आत्म-परिवर्तन का सफर अंदर से शुरू होता है। दूसरों को दोष देने या परिस्थितियों को कोसने से कुछ हासिल नहीं होगा। जब तक हम खुद को नहीं सुधारते, तब तक हमारे जीवन में सच्ची शांति नहीं आ सकती।

बजरंग दल 29 को शौर्य कुंभ में दिखाएगा ताकत, बस्तियों में दी जा रही है दीक्षा

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

बजरंग दल इंदौर में 29 मार्च को अपनी ताकत दिखाएगा। स्थानीय नेहरू स्टेडियम में शौर्य कुंभ आयोजित कर रहा है। इसमें हजारों बजरंग दल के कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। बजरंग दल के जिला प्रचार प्रमुख अन्नु गेहलोत ने बताया कि 29 मार्च को नेहरू स्टेडियम में होने वाले बजरंग दल के शौर्य कुंभ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसमें मालवा प्रांत के साथ इंदौर के कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं। इसके अलावा बस्तियों में त्रिशूल दीक्षा बड़ी संख्या में बजरंगियों द्वारा ली जा रही है। मालवा मिल चौराहे के पास गोमा की फेल में त्रिशूल दीक्षा का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में नए कार्यकर्ताओं को त्रिशूल दीक्षा विभाग मंत्री यज्ञेश राठी की मौजूदगी में दी गई।

त्रिशूल दीक्षा की आवश्यकता क्यों है, यह भी राठी ने विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि आज के परिदृश्य में हिंदू समाज को स्वयं की रक्षा के लिए शास्त्र के साथ शस्त्र की भी आवश्यकता है। हमारे इतिहास में अहिंसा को परम धर्म माना है, लेकिन इससे भी आगे आज के युग की बात करें तो धर्म की रक्षा हमें हर हाल में करना है। राठी ने बताया कि इंदौर विभाग से 25 हजार की संख्या में कुंभ में बजरंगी शामिल होंगे व मालवा प्रांत से पचास हजार से ज्यादा कार्यकर्ता नेहरू स्टेडियम में शामिल होंगे। इंदौर में अलग अलग स्थानों से बजरंग दल कार्यकर्ता पांच-पांच की पंक्ति में संचलन के रूप में नेहरू स्टेडियम में जाएंगे। जहां पर विलुप्त होते पारंपरिक खेल कबड्डी, मलखंभ जैसे खेलों का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे खेलों का संवर्धन और उत्थान का संदेश दिया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से सभी कार्यकताओं व आमंत्रित सदस्यों की प्रवेशिका बनाई जा रही है, जिससे कार्यक्रम में प्रवेश मिलेगा। बजरंग दल के कार्यकर्ता गणवेश पहनकर शामिल होंगे और त्रिशूल साथ रहेगा।

दैनिक ग्लोबल हेराल्ड
शुक्रवार 28 मार्च, 2025
महानगर
इंदौर

राज्यपाल मंगूभाई पटेल 29 को इंदौर आयेंगे

इंदौर (ग्लोबल हेराल्ड)। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल तीन दिवसीय दौरे पर 29 मार्च को इंदौर आयेंगे। इस दौरान वे यहां आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री मंगूभाई पटेल 29 मार्च को सुबह 9 बजे इंदौर आयेंगे। यहां वे सुबह 10:30 बजे से सुबह 11:25 बजे तक रेवजी रेंज में आयोजित 18वीं ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्टस शूटिंग कॉम्पिटिशन के समापन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वे दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक एमजीएम मेडिकल कॉलेज में सिकल सेल के संबंध में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। रात्रि विश्राम इंदौर में करेंगे।

नगर निगम की लापरवाही से सड़कों पर दौड़ रहे बिना नंबर के टैंकर

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

गर्मी का मौसम शुरू होते ही शहर में पानी की किल्लत बढ़ गई है। नगर निगम द्वारा रहवासियों तक पानी पहुंचाने के लिए टैंकरों की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इन टैंकरों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। नगर निगम में अटैच कई टैंकरों के पास नंबर प्लेट तक नहीं हैं और वे बिना किसी नियम-कायदे के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इन टैंकरों की तेज रफ्तार से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। इतना ही नहीं, इनमें से कई टैंकर जर्जर हालत में हैं, जिनसे लगातार पानी रिसता रहता है, जिससे बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद हो रहा है।

बिना नंबर और लीकेज टैंकरों से पानी की बबार्दी

शहर के कई जोन में ऐसे टैंकर अटैच किए गए हैं, जिनकी नंबर प्लेट गायब है और उनकी पाइप लाइन से निरंतर पानी टपकता रहता है। नगर निगम के जोन 1, 3, 6 और 14 में इन टैंकरों की स्थिति सबसे खराब है। इसके बावजूद नगर निगम के अधिकारी इस गंभीर समस्या की अनदेखी कर रहे हैं। पानी की सप्लाई के दौरान भारी मात्रा में पानी बर्बाद हो रहा है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यह पानी जहां लोगों की जरूरतें पूरी कर सकता था, वहीं अब व्यर्थ में बहकर नालियों में चला जाता है।

तेज रफ्तार टैंकरों से बढ़ रहा दुर्घटना का खतरा

बिना नंबर और जर्जर टैंकरों का सबसे बड़ा खतरा उनकी तेज रफ्तार है। निगम से अनुबंधित टैंकरों के चालक लापरवाहीपूर्वक टैंकर चलाते हैं, जिससे सड़क पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। गर्मी के मौसम में नगर निगम द्वारा अटैच किए गए इन टैंकरों की कोई जांच नहीं की जाती, जिससे बिना नंबर और लीकेज टैंकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इस पर जब नगर निगम जोन 1 के जोनल अधिकारी अतीक खान से सवाल किया गया, तो उन्होंने इसे नर्मदा प्रोजेक्ट अधिकारियों की जिम्मेदारी बताकर पल्ला झाड़ लिया। इसी तरह, जोन 3 के अतुल सिंह, जोन 6 के लोकेश शर्मा और जोन 14 के सालकराम शितोले ने भी यही बयान दिया कि टैंकरों की देखरेख नर्मदा प्रोजेक्ट के अधिकारियों द्वारा की जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि नगर निगम में टैंकरों की व्यवस्था पूरी तरह से अव्यवस्थित और लापरवाही से भरी हुई है, जिससे पानी की बबार्दी और दुर्घटनाओं की संभावना लगातार बनी हुई है।

नेताओं के दबाव में हो रही टैंकर अटैचमेंट प्रक्रिया

सूत्रों के अनुसार, नगर निगम में टैंकरों को अटैच करने की प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ गया है। नेताओं द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर टैंकरों को निगम में शामिल करवाया जा रहा है, चाहे वे नियमों के अनुरूप हों या नहीं। नगर निगम के प्रत्येक जोनल कार्यालय पर नर्मदा प्रोजेक्ट अधिकारियों को नेताओं की इच्छानुसार टैंकर अटैच करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। कई टैंकर तो ऐसे हैं जो सालभर से निगम में जुड़े हुए हैं और पानी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश की स्थिति बेहद खराब है। इसके बावजूद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी नेताओं के दबाव के कारण इन टैंकरों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आम जनता पानी की समस्या से जूझ रही है।

अग्नि सुरक्षा को देखते हुए बड़ी कार्रवाई, गैस सिलेंडर जप्त

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

इंदौर में अग्नि सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में अभियान चलाकर कार्रवाई जारी है। इसी के तहत जिला प्रशासन के अमले द्वारा आज सराफा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। इसके तहत घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग करने पर बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर जप्त किये गये।

जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एम.एल. मारु ने बताया कि जिला प्रशासन के संयुक्त जाँच दल द्वारा सराफा क्षेत्र में अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। कार्रवाई में 63 बड़ा सराफा बाजार कमला टावर स्थित दुकान में मेटल पिघलाकर ज्वेलरी निर्माण करने के लिए घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक रूप से उपयोग किया जा रहा था। जांच में 19 किलो के 1 नग भरा, 17 नग आंशिक भरे कुल 18 नग सिलेंडर तथा 14 किलो क्षमता के 9 नग आंशिक भरे सिलेंडर खाद्य विभाग अधिकारी द्वारा जप्त किये गये।

इंदौर मंडी में किसानों की फसल का पैसा 8 से 10 दिन में मिल रहा है किसानों को भुगतान

इंदौर मंडी सचिव नरेश परमार की बड़ी लापरवाहीं

कई किसानों ने की सीएम हेल्पलाइन में शिकायत

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

किसान नेता बबलू जाधव ने की मंडी बोर्ड के एमडी को शिकायत इसके बाद मंडी सचिव ने व्यापारी की खरीदी बिक्री पर लगाईं रोक इंदौर चोइथराम मंडी में किसानों को अपनी उपज लहसुन के पैसों के लिए 8 से 10 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है और अपनी फसल के पैसों के लिए सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत करना पड़ रही है मंडी सचिव किसानों के भुगतान को लेकर या उनकी समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं दिखते मंडी में अव्यवस्थाओं का अंबार होने के साथ ही किसान नेता बबलू जाधव शैलेंद्र पटेल चंदन सिंह बड़वाया आदि ने बताया कि पूर्व में इंदौर की मंडियों की अव्यवस्थाओं को लेकर हम लोगों ने मोर्चा खोला था परंतु मंडी सचिव द्वारा फर्जी एफ.आई आर दर्ज करा कर हम लोगों को दबाने का डराने का प्रयास किया गया था हम मंडी में किसानो की समस्याओं को लेकर लगातार आवाज उठाते रहेंगे उन्होंने बताया कि मंडी बोर्ड के एमडी के स्पष्ट निर्देश हैं की 2 लाख तक का भुगतान किसान को उसी दिन व्यापारी से नगद भुगतान कराया जाए परंतु इस निर्देश पर इंदौर मंडी सचिव नरेश परमार अपने अधीनस्थ आने वाली मंडीयों में1 लाख रुपए से नीचे का भी भुगतान नहीं करा पा रहे मालूम होकी इंदौर मंडी सचिव नरेश परमार की प्रति नियुक्ति दो बार बढ़ चुकी है और वे सालों से इंदौर में पदस्थ हैं एक समय से ज्यादा एक ही जगह जमे हुए हैं इन्हें तत्काल हटाना चाहिए और किसानों का जल्द से जल्द भुगतान कराया जायें।

तय समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ भवन का निर्माण किया जाये सुनिश्चित -मंत्री सिंह

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

लोकनिर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने आज गुरुवार को भोपाल में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर इंदौर में निमार्णाधीन जिला न्यायालय भवन की प्रगति की समीक्षा की और समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिए।इस दौरान प्रमुख अभियंता भवन श्री एस.आर. बघेल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि इंदौर जिला न्यायालय भवन हमारे लिए उच्च प्राथमिकता का विषय है। उन्होंने निर्देश दिए कि तय समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ भवन का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए रोज तीन शिफ्टों में कार्य किया जाएगा, सीसीटीवी कैमरों से सतत निगरानी की जाएगी। प्रमुख अभियंता (भवन) मासिक आधार पर एवं इंदौर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता साप्ताहिक आधार पर प्रगति की समीक्षा करेंगे। मंत्री श्री सिंह ने निर्देश दिए की इस परियोजना के लिए नियुक्त एसडीओ और सब-इंजीनियर पूर्णकालिक रूप से केवल इसी परियोजना पर कार्य करेंगे। किसी भी प्रकार की विलंब अथवा निर्माण कार्य में अवरोध की स्थिति ना बने, इसके लिए पहले से आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित की जाएंगी। मंत्री श्री सिंह ने कहा की निर्माण स्थल पर स्थापित प्रयोगशाला में सभी आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए, ताकि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता का समुचित परीक्षण किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा यह महत्वपूर्ण भवन समय पर एवं सर्वोत्तम गुणवत्ता के साथ तैयार हो।

मुख्यमंत्री का हेलीपेड पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया गया

इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के झाबुआ में गोपालपुरा हेलीपेड पहुँचने पर प्रभारी मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग डॉ कुँवर विजय शाह, कैबिनेट मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री निर्मला भूरिया, कैबिनेट मंत्री अनुसूचित जाति कल्याण श्री नागर सिंह चौहान, संभागायुक्त इंदौर श्री दीपक सिंह, आई जी श्री अनुराग, झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना, पुलिस अधीक्षक श्री पद्म विलोचन शुक्ल एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वागत किया गया।

श्रमिकों को संबल दे रही मध्यप्रदेश सरकार

मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना अंतर्गत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा

23 हजार 162 परिवारों को ₹ 505 करोड़ की अनुग्रह राशि का अंतरण

28 मार्च, 2025 | दोपहर 2:30 बजे
मंत्रालय, भोपाल

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

संबल योजना में
गिग वर्कर्स भी शामिल

- संबल योजना में 1 करोड़ 74 लाख से अधिक श्रमिक भाई-बहन पंजीयन करा चुके हैं।
- अब तक कुल 6 लाख 58 हजार से अधिक प्रकरणों में राशि ₹5927 करोड़ से अधिक का हितलाभ वितरण किया गया है।
- पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर ₹2 लाख, दुर्घटना मृत्यु पर ₹4 लाख की अनुग्रह सहायता।
- पंजीकृत श्रमिक की स्थायी अपंगता पर ₹2 लाख, आंशिक स्थाई अपंगता पर ₹1 लाख की सहायता।
- पंजीकृत श्रमिक व पंजीकृत श्रमिक के परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर ₹5 हजार की अंत्येष्टी सहायता।
- सभी संबल हितग्राहियों को आयुष्मान भारत निरामयम् योजना अंतर्गत पात्र श्रेणी में चिन्हित किया गया है।
- संबल हितग्राहियों को रियायती दरों पर राशन की सुविधा।
- संबल हितग्राहियों के बच्चों को महाविद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत महाविद्यालय (मेडिकल, विधि, इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक आदि) में शिक्षा हेतु सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
- पंजीकृत महिला श्रमिक व पुरुष श्रमिक की पत्नी को प्रसूति सहायता योजना अंतर्गत कुल ₹16 हजार की राशि की सहायता।

D-11216/24

सीधा प्रसारण Webcast.gov.in/mp/cmevents @Cmmadhyapradesh @jansampark.madhyapradesh @Cmmadhyapradesh @jansamparkMP JansamparkMP

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी
आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2025

तकनीक में उलझे डोंगरिया गांव के किसान, किसी और की गलती का भुगतना पड़ सकता है गंभीर खामियाजा

बालाघाट ■

बालाघाट जिले का एक ऐसा गांव, जो शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं से वंचित होने की कगार पर है। यहां निवासरत एक-दो नहीं, बल्कि सैकड़ों किसान सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए अपात्र हो सकते हैं। इस स्थिति को लेकर किसानों ने अपनी समस्याएं जिला स्तर तक पहुंचाई हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं हो सका है, जिससे वे परेशान हैं।

गौरतलब है कि इस समय किसान की फार्मर आईडी बनाने का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आगामी 31 मार्च तक सभी किसानों की फार्मर आईडी बनानी अनिवार्य है। निर्धारित समयावधि के बाद जिन किसानों की आईडी नहीं बन पाएगी, वे शासन की कई योजनाओं से वंचित हो जाएंगे और कई लाभों से हाथ धोना पड़ सकता है। यह पूरा मामला बालाघाट जिले की परसवाड़ा तहसील के ग्राम डोंगरिया का है, जहां के किसान फार्मर आईडी बनाने के लिए परेशान हैं। किसानों के अनुसार, उन्होंने कई बार प्रयास किए, लेकिन उनकी फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है। किसान चिंतित हैं कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका पंजीकरण नहीं होता है, तो वे न केवल भविष्य में योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाएंगे, बल्कि मौजूदा योजनाओं से भी हाथ धो सकते हैं। किसानों का कहना है कि जब वे फार्मर आईडी बनाने के लिए राजस्व विभाग के पास जाते हैं, तो उनका गांव परसवाड़ा तहसील में दर्ज नहीं दिखता, बल्कि दूसरी तहसील में दर्ज होने की जानकारी मिलती है, जिससे फार्मर आईडी बनवाने में समस्या आ रही है। हालांकि, राजस्व विभाग इस समस्या को लेकर परेशान है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। ग्राम के किसान अशोक कटरे ने बताया कि यदि समय पर उनकी फार्मर आईडी नहीं बन पाती है, तो किसानों को कृषि सब्सिडी, फसल बीमा, कृषि ऋण, फसलों की बिक्री, और प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस मामले पर परसवाड़ा तहसीलदार वर्षा झारिया ने बताया कि तकनीकी समस्या के कारण डोंगरिया गांव दूसरी तहसील में दर्ज हो रहा है, जिसके कारण किसानों की फार्मर आईडी बनाने में समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि इस समस्या की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी गई है और भोपाल से भी बातचीत की गई है। जैसे ही समस्या का समाधान होगा, किसानों की फार्मर आईडी बनाई जाएगी। हालांकि, फार्मर आईडी बनाने के लिए निर्धारित समय सीमा के बारे में उन्होंने कहा कि उच्चाधिकारियों के निदेर्शों के अनुसार ही कार्य किया जाएगा।

ससुराल की जायदाद के लिए सगाई के बाद ही कर डाला कांड..

बेतुल। मध्यप्रदेश के बैतूल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां ससुराल की संपत्ति हड़पने के लालच में एक युवक ने सगाई के बाद ही अपने होने वाले साले को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने नाबालिग को मौत के घाट उतारने के बाद उसके शव को अपने साथी के साथ मिलकर जंगल में दफना दिया था लेकिन पुलिस की जांच में उसके जुर्म का पदार्फाश हो गया। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 19 मार्च को छिंदवाड़ा के थाना आठनेर में झामलाल निवासी वनग्राम ने अपने 15 साल के नाबालिग बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका बेटा 14 मार्च से लापता है।

सच्चा भक्त मन से सरल और स्वच्छ होता है

श्री श्री आनन्दमूर्ति

ग्लोबल हेराल्ड

एक बार एक साधक ने पूछा, बाबा, भक्त को हम कैसे पहचानते हैं? भक्ति का अर्थ है अपने मन को सभी सांसारिक आकर्षणों से हटाकर परमपुरुष की ओर केंद्रित करना। जब व्यक्ति अपने मन को ब्रह्मांड से जोड़ता है, तो उसे भक्ति कहते हैं, लेकिन जब वह सांसारिक चीजों में उलझ जाता है, तो उसे आसक्ति कहा जाता है। भक्ति का असली अर्थ यही है कि हम अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को बाहरी चीजों से हटा कर केवल परमपुरुष की ओर लगाएं। यदि मन किसी अन्य चीज की ओर आकर्षित होता है, तो वह भक्ति नहीं, बल्कि लगाव कहलाता है। मनुष्य को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली श्रेणी ऐसे लोगों की है जो अपनी सच्ची भावनाएं छिपाते हैं।

वे अपने वास्तविक विचारों को मन में रखते हैं और उन्हें प्रकट नहीं करते। दूसरी श्रेणी के लोग जो सोचते हैं, वह कभी नहीं कहते, बल्कि कुछ और बोलते हैं। उनके शब्द उनके वास्तविक विचारों को प्रकट नहीं करते, लेकिन वे जो कहते हैं, उसे निभाते जरूर हैं। तीसरी श्रेणी के लोगों की सोच, वाणी और कर्म तीनों अलग-अलग होते हैं। वे कुछ सोचते हैं, कुछ और कहते हैं और फिर कुछ और करते हैं। ऐसे लोग अक्सर समाज को धोखा देते हैं और लोगों का विश्वास खो देते हैं। तीसरी श्रेणी के लोगों के भीतर तीन व्यक्तित्व हमेशा एक-दूसरे से टकराते रहते हैं। पहला व्यक्तित्व सोचता है, दूसरा तय करता है कि क्या कहा जाए और क्या छिपाया जाए, और तीसरा कुछ और ही कर बैठता है। यह आंतरिक संघर्ष व्यक्ति को अस्थिर और अविश्वसनीय बना देता है। उदाहरण के लिए, एक नेता ने सड़क बनाने का वादा किया, लेकिन जब समय आया, तो उसने टालमटोल कर दी। इस प्रकार के लोग केवल बहाने बनाते हैं और कभी भी अपनी बातों पर अमल नहीं करते। धीरे-धीरे, लोग उनका सम्मान खो देते हैं और अंततः उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता है। भक्ति मार्ग में इस तरह की बातें नहीं होतीं। सच्चा भक्त मन से सरल, स्वच्छ और निर्मल होता है। वह वही सोचता है, वही कहता है और वही करता है। उसकी नीयत और कर्म में कोई अंतर नहीं होता। दूसरी श्रेणी के लोग भले ही अपने विचारों को प्रकट न करें, लेकिन वे जो कहते हैं, वही करते हैं। ऐसे लोग अपने कार्यों से अपनी सच्चाई साबित करते हैं और इसी वजह से समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। लेकिन वास्तव में महान व्यक्ति वे होते हैं जिनका मन, वाणी और कर्म एक समान होते हैं। वे बिना किसी झूठ और छल-कपट के वही कहते और करते हैं जो वे सोचते हैं। वे ईमानदार होते हैं और उनके मन में किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होता। भक्ति का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अवस्था है जिसमें मनुष्य अपने मन को परमपुरुष की ओर मोड़ता है। जो लोग सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, उनके मन में कोई झगड़ा या संघर्ष नहीं होता। उनका मार्ग स्वच्छ और स्पष्ट होता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से परमपुरुष की ओर बढ़ता है, उसके जीवन से सभी बाधाएं धीरे-धीरे समाप्त हो जाती हैं। भक्ति मार्ग पर चलने वालों को चाहिए कि वे अपने पथ से सभी बाधाओं को हटा दें और इसे सरल, साफ और स्वच्छ बनाएं।

प्रस्तुति : दिव्यचेतनानन्द अवधूत

चेट्रीचंड्र महोत्सव पर आयोलाल झूलेलाल के जयघोष के साथ मनेगा सिंधियत दिवस

बालाघाट ■

जिले में धार्मिक अनुष्ठान एवं रचनात्मक आयोजन के साथ इष्टदेव भगवान झूलेलाल सांई का 1075 वां जन्मोत्सव सिंधियत दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान झूलेलाल का अभिषेक, हवन-पूजन तथा स्वजातीय महिलाए स्कूटर रैली एवं पुरुष बाइक रैली निकालेंगे। जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी होगा। शहर में भव्य शोभायात्रा निकलेगी। आयोलाल झूलेलाल की चहुंओर गूंज होगी। सिंधियत दिवस की रूपरेखा से अवगत कराने पूज्य सिंधी पंचायत ने सिंधु भवन में गुरूवार को आवश्यक जानकारी दी।

चेट्रीचंड्र महोत्सव को लेकर पूज्य सिंधी पंचायत संरक्षक रमेश रंगलानी ने बताया कि 29 मार्च को सुबह 10 से शाम 3 बजे तक विशाल स्वास्थ्य शिविर जिला अस्पताल के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। सभी प्रकार की बीमारियों करीब 67 प्रकार की जांच की जाएगी और विषय विशेषज्ञ जांच कर परामर्श देते हुए दवाईयां वितरित करेंगे। वृद्धजनों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। सर्वसमाज के लिए यह आयोजन होगा। शाम को 5 बजे समाज की महिलाएं स्कूटर रैली निकालेंगी। शाम 6.30 बजे बढ़ते कदम संस्था लगभग 11 हजार दीये प्रज्वलित करेंगी। रात्रि 9 बजे प्रख्यात सिंधी बॉलीवुड गायक अजय मुकेश एवं प्रियंका केशवानी की आवाज में एक शाम झूलण के नाम आयोजन में गीतों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। पूज्य सिंधी पंचायत अध्यक्ष अमर मंगलानी ने बताया कि 30 मार्च को सुबह 8.30 बजे सिंधु भवन से बाइक रैली निकाली जाएगी।

गुना में मरीजों की जगह खरबूजे लेकर पहुंची एम्बुलेंस, वीडियो बनाया, ड्राइवर मौके से फरार

गुना ■

गुना में मरीजों की जगह खरबूजे लेकर पहुंची एम्बुलेंस... ये सुनकर आप भी हैरान होंगे कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। ये मध्य प्रदेश के गुना जो एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार सरकारी संसाधनों के बेतहाशा दुरुपयोग और प्रशासनिक लापरवाही देखने को मिल रही है।

गुना में उत्तर प्रदेश की सरकारी एंबुलेंस को मरीजों के इलाज के लिए नहीं, बल्कि खरबूजे ढोने के लिए इस्तेमाल किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस एंबुलेंस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सॉफ तौर पर एंबुलेंस पर लिखा हुआ है। यानी कि यह उत्तर प्रदेश से चलकर गुना पहुंची है। इसे पहचान छिपाने के लिए पीले रंग के तिरपाल से भी इस दौरान ढंकने की कोशिश यहां की गई। जब स्थानीय लोगों ने इस नजारे को देखा तो वे भी हैरान रह गए। दांतों तले उंगलियां दबा ली। गुना पुलिस ने भी शायद एंबुलेंस समझकर कोई कार्रवाई नहीं की। यहां पुलिस की कार्रवाई पर वही सवाल खड़े हो जाते हैं कि बिना नंबर प्लेट के एम्बुलेंस आखिर गुना की सड़कों पर क्यों दौड़ रही है। सड़कों पर दौड़ती इस एंबुलेंस को देखकर पहले तो लोगों को लगा कि कोई गंभीर मरीज अस्पताल ले जाया जा रहा होगा, लेकिन जब यह एंबुलेंस सीधे सब्जी मंडी आढ़त पहुंची, तो लोग चौंक गए। वहां पहले से मौजूद व्यापारी और ग्राहक भी उस वक्त अवाक रह गए, जब उन्होंने देखा कि मरीजों की जगह एंबुलेंस से खरबूजे उतारे जा रहे हैं और मंडी में मोल भाव कर बेचे जा रहे हैं। इस दौरान कई लोगों ने इस पूरे मामले का वीडियो भी बना लिया और वीडियो वायरल होते ही मामला गरमाने लगा और मामले की पोल खुल गई। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को देखिए जिसने एक नहीं कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कि क्या सरकारी संसाधनों का इतना बड़ा दुरुपयोग बिना किसी प्रशासनिक मिलीभगत के संभव हो सकता है? आपको बता दें गुना में यह पहली बार नहीं हुआ है जब सरकारी सेवाओं का गलत इस्तेमाल किया गया हो। कुछ दिन पहले ही एक मासूम की मौत इसलिए हो गई थी क्योंकि उसे समय पर एंबुलेंस नहीं मिली थी। तब भी प्रशासन चुप्पी साधे रहा था। दूसरी बार जब एंबुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाने के बाद मासूम नाबालिक ने दम तोड़ दिया था। मामला गरमाया था। परिजनों ने शिकायत की थी।

पे टू पे मामले में वारासिवनी जनपद अध्यक्ष माया उइके पर गिरेगी गाज

बालाघाट ■

शासकीय योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं के नाम पर आमजनों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाली पे टू पे सोशियल फाउंडेशन जयपुर की आग के लपेटे में अब जनपद अध्यक्ष माया उइके भी आते हुए नजर आ रही हैं। इस मामले में 26 मार्च को ग्राम रमरमा के दो ग्रामीणों विनोद पिता सुरेन्द्र परते व राकेश पिता झनक लाल बिसेन ने एक लिखित शिकायत पुलिस थाना वारासिवनी में दी हैं।

उन्होंने जनपद वारासिवनी की अध्यक्ष माया उइके, रमरमा निवासी अल्फिया कादर खान एवं रमरमा के रोजगार सहायक विनोद पिता सुमेर सिंह भलावी पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर 550-550 रुपए की राशि लेने और उनके साथ धोखाधड़ी कर अवैध रुप से आर्थिक लाभ अर्जित करने का आरोप लगाया हैं। थाने में की गई शिकायत अनुसार जनपद वारासिवनी की अध्यक्ष माया उइके रमरमा के निकटस्थ ग्राम नांदगांव से जनपद सदस्य के रुप में चुनकर आई हैं। विनोद भलावी रमरमा का रोजगार सहायक हैं। जनपद अध्यक्ष माया उइके ने इन ग्रामीणों को जानकारी दी थी कि भारत सरकार नीति आयोग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना संचालित की जा रही हैं। एक मुश्त 550 रुपए जमा करने पर बेटी के विवाह पर डेढ़ लाख रुपए नकद और यदि बीच में परिवार का कोई सदस्य बीमारी से ग्रस्त होता हैं, तो उसका समस्त खर्चा भी शासन वहन करता हैं।

दीपक तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी, निकिता ने 7 दिन बाद किया पोस्ट और

धार। मध्यप्रदेश में बॉयफ्रेंड के सुसाइड से दुखी युवती ने भी अपनी जान दे दी। मामला धार जिले का है जहां प्रेमी जोड़े की प्रेम कहानी के दर्दनाक अंत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। अलग अलग समाज के होने के कारण यहां प्रेमी युगल ने 7 दिन के अंदर अपनी जान दे दीं। दोनों ने पहले तो अपने अपने परिजन को मनाने की पूरी कोशिश की लेकिन जब परिवार नहीं माने तो पहले लड़के दीपक ने सुसाइड किया और फिर 7 दिन बाद लड़की निकिता ने भी जहर खाकर खुदकुशी कर ली। धार जिले के नौगांव की रहने वाली 20 साल की निकिता ने 22 मार्च 2025 को जहर खाकर खुदकुशी कर ली।

एमपी की बड़ी फैक्ट्री होगी कुर्क, कर्मचारियों का बकाया है करीब 17.55 करोड़

नीमच ■

मध्यप्रदेश के नीमच जिले की जावद तहसील के नयागांव में बंद हो चुकी सीसीआई (सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) फैक्ट्री की कुर्की की तारीख कोर्ट ने तय कर दी है। जावद तहसील कोर्ट ने फैक्ट्री की कुर्की के संबंध में आदेश जारी करते हुए कुर्की की तारीफ 2 अप्रैल तय की है।

कोर्ट ने फैक्ट्री की कुर्की के दौरान जिम्मेदार अधिकारियों को मौके पर मौजूद रहने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने ये भी कहा है कि किसी जिम्मेदार के कुर्की के दौरान उपस्थित न होने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। नयागांव की सीसीआई फैक्ट्री में काम करने वाले 55 मजदूरों का 17 करोड़ 55 लाख 59 हजार 405 रुपये का वेतन बकाया है। इसके बाद फैक्ट्री के स्क्रैप को नीलाम करने की तैयारी की जा रही थी और टेंडर भी निकाल दिया गया था। कर्मचारियों के बकाया वेतन की वसूली के लिए 22 मार्च को तहसीलदार जावद सीसीआइ फैक्ट्री की संपत्ति कुर्क करने नयागांव भी पहुंचे थे लेकिन तब फैक्ट्री का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद न होने के कारण कुर्की नहीं हो पाई थी। अब न्यायालय तहसीलदार जावद ने फैक्ट्री प्रबंधन के विरुद्ध आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक 2 अप्रैल को फैक्ट्री की सम्पत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।

Change in Name

Change in Name **I Suresh Maheshwari S/o Dhannalal Maheshwari** here by Declare That I have changed My Name as **Suresh Maheshwari Tapadia S/o Dhannalal Maheshwari** so, from now and in future I will be known by my new name **Suresh Maheshwari Tapadia S/o Dhannalal Maheshwari**.

Add : Rajmohalla Chouraha Dilasan Achar Ke Pass, 222 Jawahar Marg, Indore, Indore, Madhya Pradesh - 452002

कैसे रूक पायेगा राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण

रमेश सर्राफ धमोरा
लेखक
ग्लोबल हेराल्ड

हमारे देश के राजनेताओं में दिन-प्रतिदिन नैतिकता कम होती जा रही है। कई बड़े नेता आए दिन विवादास्पद बयान देखकर चचाओं में बने रहते हैं। वहीं बहुत से निर्वाचित विधायकों, सांसदों, मंत्रियों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों पर अपराधिक मामले दर्ज हो रहें हैं। जिससे राजनीति के क्षेत्र में काम करने वालों की छवि खराब होती जा रही है। देश की राजनीति में आज अपराध का इतना घालमेल हो गया है कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा जनप्रतिनिधि अपराधी है और किसकी छवि स्वच्छ है। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के नेता बनने से जहां राजनीतिक दागदार हुई है। वहीं नेताओं की जनता की दूरी भी बढ़ने लगी है। मौजूदा समय में राजनीतिक व्यवसाय बन चुकी है। राजनीति में वही लोग सफल होते हैं जो या तो बड़े नेताओं के परिवार से है या फिर बहुत पैसे वाले हैं। राजनीति के क्षेत्र में अब सेवा, संगठन, वफादार कार्यकताओं का कोई महत्व नहीं रह गया है। राजनीति पूरी तरह पैसों की चकाचौंध में लिप्त हो गई है।

एक समय था जब धरातल पर काम करने वाला पार्टी कार्यकर्ता आगे चलकर जनप्रतिनिधि बनता था। जमीन से उठकर आगे आने वाला नेता आम जनता से जुड़ा रहता था और वह जनता के सुख-दुख से वाकिफ भी होता था। इसलिए वह आमजन के हित में काम करता था। मगर अब लोग पैसे के बल पर पैराशूट से उतरकर राजनीति करने लगे हैं। वह पैसे के बल पर ही चुनाव जीत जाते हैं। इसलिए उन्हें आमजन की समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं रहता है। ऐसे नेता पांच सितारा संस्कृति के वाहक होते हैं। ऐसे नेता राजनीति में आने के लिए पहले खूब पैसा खर्च करते हैं और जब किसी पद पर पहुंच जाते हैं तो जमकर भ्रष्टाचार कर पैसा कमाते हैं। ऐसे लोगों के कारण ही आज राजनीति समाज सेवा की बजाय व्यवसाय बन गई है। 1971 के लोकसभा चुनाव में झुंझुनू सीट पर देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने के कृष्ण कुमार बिड़ला को हराने वाले शिवनाथ सिंह गिल को मैंने 1998 से 2003 में विधायक के रूप में देखा है। वह अपने क्षेत्र से जयपुर जाते या अपने घर से विधानसभा जाते हमेशा सरकारी बस का ही उपयोग करते थे। कभी निजी गाड़ियों से नहीं घूमते थे। इसी के चलते उन्होंने राजनीति में 50 साल लंबी पारी खेली थी। वह ईमानदार थे इसीलिए ईमानदारी से रहते थे। आज हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों के छोटे-छोटे कार्यकर्ता भी कई लाख रूपयों की महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। पार्टी का कोई नेता उनसे यह नहीं पूछता है कि इतनी महंगी गाड़ियां खरीदने के लिए पैसे कहां से आता है। सबको पता है की राजनीति में आज छूट-भैया नेता भी सत्ता की दलाली में पैसा कमा रहे हैं। दलाली के पैसों में बड़े नेताओं का भी हिस्सा होता है। इसीलिए उनकी तरफ कोई अंगुली नहीं उठाता हैं। चुनाव सुधार पर काम करने वाली एक गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि देश के 45 प्रतिशत विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस संगठन ने देश के 28 राज्यों और विधानसभा वाले तीन केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 4123 विधायकों में से 4092 के चुनावी हलफनामे का विश्लेषण किया है। जिसमें आंध्र प्रदेश के सबसे ज्यादा 174 में से 138 यानी

79 प्रतिशत विधायकों ने जबकि सिक्किम में सबसे कम 32 में से सिर्फ एक विधायक 3 प्रतिशत ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। तेलुगु देशम पार्टी के सबसे ज्यादा 134 विधायकों में से 115 यानि 86 प्रतिशत पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उक्त रिपोर्ट से पता चला कि 1861 विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। इसमें 1205 पर हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। रिपोर्ट के अनुसार 54 विधायकों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के आरोप हैं। वहीं 226 पर धारा 307 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत हत्या की कोशिश के आरोप हैं। इसके अलावा 127 विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले दर्ज हैं। इनमें 13 पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 376 और 376 (2)(द) के तहत बलात्कार का आरोप है। धारा 376 (2)(द) एक ही पीड़ित के बार-बार यौन उत्पीड़न से संबंधित है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार 543 लोकसभा सदस्यों में से 251 (46 प्रतिशत) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनमें से 27 को दोषी ठहराया गया है। रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा में चुने जाने वाले आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे उम्मीदवारों की यह सबसे बड़ी संख्या है। कुल 233 सांसदों (43 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए थे। जबकि 2014 में 185 (34 प्रतिशत), 2009 में 162 (30 प्रतिशत) और 2004 में 125 (23 प्रतिशत) सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2024 में लोकसभा के लिये चुने गये 251 उम्मीदवारों में से 170 (31 प्रतिशत) पर बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। विश्लेषण से पता चला कि यह 2019 में 159 (29 प्रतिशत) सांसदों, 2014 में 112 (21 प्रतिशत) सांसदों और 2009 में 76 (14 प्रतिशत) सांसदों की तुलना में भी वृद्धि है। एडीआर के अनुसार 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी बीजेपी के 240 विजयी उम्मीदवारों में से 94 (39 प्रतिशत) ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं। कांग्रेस के 99 विजयी उम्मीदवारों में से 49 (49 प्रतिशत) ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं और समाजवादी पार्टी के 37 उम्मीदवारों में से 21 (45 प्रतिशत) पर आपराधिक आरोप हैं। विश्लेषण में पाया गया कि 63 (26 प्रतिशत) बीजेपी उम्मीदवार, 32 (32 प्रतिशत) कांग्रेस उम्मीदवार और 17 (46 प्रतिशत) समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इसमें कहा गया है कि सात (24 प्रतिशत) टीएमसी उम्मीदवार, छह (27 प्रतिशत) डीएमके उम्मीदवार, पांच (31 प्रतिशत) टीडीपी उम्मीदवार और चार (57 प्रतिशत) शिवसेना उम्मीदवार गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार केरल के 20 में से 19 (95 प्रतिशत) सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें से 11 गंभीर अपराधों से जुड़े हैं। तेलंगाना के 17 में से 14 (82 प्रतिशत), ओडिशा के 21 में से 16 (76 प्रतिशत), झारखंड के 14 में से 10 (71 प्रतिशत) और तमिलनाडु के 39 में से 26 (67 प्रतिशत) सांसदों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में लगभग 50 प्रतिशत सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरी ओर हरियाणा 10 और छत्तीसगढ़ 11 सांसद में केवल एक-एक सांसद पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंजाब के 13 में से 2, असम के 14 में से 3, दिल्ली के 7 में से 3, राजस्थान के 25 में से 4, गुजरात के 25 में से 5 और मध्य प्रदेश के 29 में से 9 सांसदों पर आपराधिक मामले लंबित हैं। एक जनवरी 2025 तक वर्तमान या पूर्व विधायकों के खिलाफ कुल 4,732 आपराधिक मामले लंबित थे। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 1,171 मामले दर्ज हैं। ओडिशा (457), बिहार (448), महाराष्ट्र (442), मध्य प्रदेश (326), केरल (315), तेलंगाना (313), कर्नाटक (255), तमिलनाडु (220), झारखंड (133) और दिल्ली (124) मुकदमे लंबित हैं। उपरोक्त आंकड़ों को देखने से लगता है कि हमारे देश की राजनीति में आपराधियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यदि समय रहते इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो यह देश के लिए एक बड़ा नासूर बन जाएगी। एक समय ऐसा होगा जब राजनीति का पूरी तरह अपराधीकरण हो जाएगा और स्वच्छ छवि के लोग राजनीति से दूर होते चले जाएंगे। ऐसी स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं होगी। सरकार को भी इस दिशा में कड़े कदम उठाने होंगे तभी राजनीति में बढ़ती अपराधियों की संख्या पर लगाम लग पाएगी।

(नोटः इस लेख में ये दिए गए विचार लेखक के अपने विचार हैं)

एमपी में महसूस हुए भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग

सिंगरौली ■

मध्यप्रदेश के सिंगरौली में गुरुवार की दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए हैं। इसकी जानकारी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दी। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई है। भूकंप के झटका दोपहर 3 बजकर 7 मिनट पर आया था। जिसका केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर की गहराई में था।

भूकंप के झटके सिंगरौली के आसपास के जिलों में भी महसूस किए गए। लोगों ने भूकंप के कारण घर से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पनाह ले ली। हालांकि, लोगों को धरती की कंपन का महसूस नहीं हुआ। जिला प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है कि किसी प्रकार के कोई भी नुकसान की जानकारी नहीं है। रिक्टर स्केल पर 3-7 तीव्रता वाले भूकंप को हल्का माना जाता है। इससे पहले 17 फरवरी को सिंगरौली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तब इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई थी।

ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कर्मचारी पर तेंदुए ने किया अटैक, मचा हड़कंप

जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर के खमरिया स्थित आयुध निमार्णी (ऑर्डिनेंस फैक्ट्री) फैक्ट्री में गुरूवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कर्मचारी पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुआ फैक्ट्री के बारूद गोदाम में बोरियों के पीछे छिपा और जैसे ही कर्मचारी वहां पहुंचा तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। कर्मचारी ने किसी तरह अपनी जान बचाई और भागते हुए बाहर आया। फैक्ट्री में तेंदुए के द्वारा हमला किए जाने की खबर से हड़कंप मच गया। खमरिया की आयुध निमार्णी फैक्ट्री में गुरुवार की सुबह भंडारण से बारूद लेने के लिए गए एक कर्मचारी पर अचानक तेंदुआ ने हमला कर दिया था। तेंदुआ बोरियों के पीछे छिपा हुआ था। तेंदुए के हमले में कर्मचारी घायल हुआ था जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहले इस तरह की बात सामने आई थी कि फैक्ट्री में मादा तेंदुआ है जिसके साथ उसके दो शावक भी हैं। आयुध निमार्णी फैक्ट्री में कर्मचारी पर तेंदुए के हमले की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सर्चिंग शुरू की। तेंदुआ मैग्जीन में बोरियों के पीछे छुपा हुआ था। क्योंकि अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था इसलिए तेंदुए को बेहोश कर वन विभाग टीम ने रेस्क्यू किया है और पिंजरे में बंद कर अपने साथ ले गई है।

कांग्रेस विधायक द्वारा साधु-संतों की तुलना सांड से करने पर बवाल, विधायक ने वीडियो जारी कर दी सफाई

क्या कांग्रेस हिंदू समाज को समाप्त करने की साजिश

भोपाल ■

मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक द्वारा साधु संतों की तुलना सांड से करने पर सियासी जंग छिड़ गई है। जहां प्रदेश भर के साधु संत इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं भाजपा के नेता कांग्रेस को लगातार घेर रहे हैं। बवाल मचने के बाद विधायक डॉ राजेंद्र सिंह ने अपने बयान पर सफाई दी है। सहकारिता और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने हमला बोलते हुए कांग्रेस नेतृत्व से विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

मामले में मचे बवाल के बाद कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि मेरी बात की लोगों ने अलग-अलग व्याख्या की है। साधु संतों महामंडलेश्वर का काम किसी पार्टी का काम करना नही है। साधु संतों को किसी दल से सहानुभूति हो सकती है, लेकिन प्रचार करना ठीक नहीं है। हम लोग सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं। कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह द्वारा साधु-संतों की तुलना सांडों से करने वाले विवादित बयान पर मध्यप्रदेश के सहकारिता और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने हमला बोलते हुए कांग्रेस नेतृत्व से विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और यह भी कहा कि यदि कांग्रेस इस मामले में कोई कदम नहीं उठाती है, तो इसे पार्टी का आधिकारिक बयान माना जाएगा।

कांग्रेस विधायक ने बताया था सांड

गौरतलब है कि प्रदेश के पूर्व मंत्री व अमरपाटन से कांग्रेस विधायक डॉ. राजेंद्र कुमार सिंह ने साधु-संतों को लेकर विवादित बयान दिया था। सतना में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने साधु-संतों और महामंडलेश्वरों सांड बताया था। राजेंद्र कुमार ने कहा था कि संयोग ऐसा कि राम मंदिर आ गया, उधर महाकुंभ आ गया। कितना प्रचार हुआ, मैंने तो गणित लगाया, 10-12 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं गए। उन्होंने आगे कहा था कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, इंजीनियर हूं। 60 करोड़ लोग, वाट्सएप यूनिवर्सिटी ने लोगों के दिमाग में भर दिया। फिर इन्होंने साधु-संत, संन्यासी, बाबा बैरागी और महामंडलेश्वरों को छोड़ दिया जनता के बीच, जाओ हिंदुत्व की बात करो, भाजपा का प्रचार करो, सनातन की बात करो और ये सांड, चर रहे हैं दूसरों का खेत।

इससे बड़ा कुकृत्य और कुछ नहीं हो सकता

मंत्री सारंग ने विधायक राजेंद्र सिंह के बयान की निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस हिंदू देवी-देवताओं और सनातन धर्म का लगातार अपमान कर रही है। अब तो हद हो गई, हमारे पूज्य साधु-संतों की तुलना सांडों से की जा रही है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यह टिप्पणी उस मंच से की गई जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मौजूद थे, यह दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही लेकिन इससे बड़ा कुकृत्य और कुछ नहीं हो सकता।

सेंट्रल जेल : ईद पर नहीं होगी खुली मुलाकात

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को इस बार परिजनों से खुली मुलाकात करने का मौका नहीं मिलेगा। जेल प्रशासन की ओर से परिसर में नोटिस चस्पा कर दिया है। जिसके चलते परिजनों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। हर साल कैदी रक्षाबंधन, ईद, होली और दीपावली जैसे त्योहारों में खुली मुलाकात करते हैं। दरअसल, जेल में निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसके चलते ईद पर खुली मुलाकात नहीं हो पाएगी। हालांकि, सामान्य मुलाकात की व्यवस्था जारी रहेंगी। इधर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पत्र में लिखा है कि ईद पर होने वाली खुली मुलाकात बंद रहेगी, लेकिन सामान मुलाकात दी जाएगी।

कोतमा में आमरण अनशन कर रहे आंदोलनकारी को जबरन उठाया, भेजा जिला चिकित्सालय

अनूपपुर ■

अनूपपुर के कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फैली अव्यवस्था और चिकित्सकों की कमी को लेकर स्थानीय नागरिक बीते चार दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। चौथे दिन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जबरन आंदोलनकारियों को एंबुलेंस में बैठाकर जिला चिकित्सालय भेज दिया।

कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरने और व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने की मांग को लेकर पूर्व भाजपा पार्षद देवशरण और अधिवक्ता दीपक पटेल 24 मार्च से आमरण अनशन पर बैठे थे। 27 मार्च को एसडीएम कोतमा अजीत तिर्की, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आरके वर्मा, थाना प्रभारी और पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर इलाज की जरूरत का हवाला देते हुए आंदोलनकारियों को जबरन जिला अस्पताल ले गए। एसडीएम अजीत तिर्की ने बताया कि बिना अनुमति अनशन किया जा रहा था। वहीं, सीएमएचओ आरके वर्मा ने कहा कि चार दिनों से भूखे-प्यासे रहने के कारण उनकी सेहत बिगड़ रही थी, इसलिए उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अव्यवस्था और बदहाली लगातार सुर्खियों में बनी हुई है।

प्रशासन की कार्रवाई पर आक्रोश

गुरुवार को राजस्व, स्वास्थ्य और पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद, दोनों अनशनकारियों को जबरन हटाया गया। बलपूर्वक की गई इस कार्रवाई को लेकर नगर में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। सीएमएचओ डॉ. आरके वर्मा ने बताया कि सप्ताह में दो दिन महिला एवं शिशु रोग विशेषज्ञ कोतमा में उपलब्ध रहेंगे।

मध्य प्रदेश में इस सीजन में पहली बार 41 डिग्री पार पहुंचा दिन का पारा, मार्च में 2 दिन चलेगी लू

भोपाल ■

प्रदेश के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले दो दिन से प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ा है। दिन में तीखी धूप खिल रही है। इस कारण लोग बचने के तरीके ढूंढते हैं। दूसरी ओर, कई शहरों में पारा सामान्य से चार से पांच डिग्री तक अधिक है। गुरुवार को प्रदेश में इस सीजन में पहली बार 41 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। खजुराहो सबसे गर्म रहा यहां का अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, प्रदेश के 6 जिलों में 40 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार मार्च के आखिरी दो दिनों में लू चलने के आसार हैं।

मार्च के आखिरी दो दिन प्रदेश में चलेगी लू

मार्च के आखिरी दो दिन प्रदेश में लू का असर रह सकता है। मालवा-निमाड़ यानी, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में लू का असर रहने की संभावना है। इनमें रतलाम, उज्जैन, खरगोन, खंडवा, धार आदि शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार, सामान्यतः दिन का तापमान 40 डिग्री से अधिक या सामान्य से 4.6 डिग्री तक अधिक हो तो हीट वेव यानी लू की स्थिति मानी जाती है। अगले तीन 4 महीने तेज गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग ने मार्च से मई तक 15 से 20 दिन हीट वेव चलने का अनुमान जताया है। अप्रैल-मई में हीट वेव का असर ज्यादा हो सकता है।

मकान की दीवार गिरने से हादसा, 1 मजदूर की मौत, ऑपरेशन जारी

बुरहानपुर ■

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में गुरुवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। शहर के पीपल घाट रोड पर गुरुवार को एक निमार्णाधीन क्षेत्र में सीवरेज पाइप डालने के दौरान एक मकान की दीवार गिरने से तीन मजदूर मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से बचाव कार्य जारी है।

हादसे की सूचना मिलते ही अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, सीएसपी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। प्रशासन ने जेसीबी की मदद से मलबा हटाया। इस दौरान एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। तीसरे मजदूर को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से मौके पर भीड़ को हटाया। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ।

ट्रेंडेस्टिक वेंचर्स कंपनी के कार्यालय पर पुलिस का धावा

बेरोजगारों को नौकरी देने के नाम पर ठगी करने का आरोप

बालाघाट ■

कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को बूढ़ी स्थित रेलवे क्रासिंग के पास संचालित ट्रेंडेस्टिक वेंचर्स कंपनी के कार्यालय पर धावा बोला। पुलिस ने वहां काम कर रहे कर्मचारियों को अपने साथ थाना लेकर आई। शाम तक पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी। आरोप है कि जिले के बेरोजगारों को नौकरी देने के नाम पर पैसे की ठगी कर रहे थे। एक युवती ने रजिस्ट्रेशन के नाम पर पांच सौ, ट्रेनिंग एवं रूम के लिए 2500 रुपए लेने के आरोप लगाए हैं।

बूढ़ी निवासी सौरभ लोधी ने बताया कि यह कंपनी किसी दूसरे राज्य की है। यहां काम करने वाले कर्मचारी जिले के बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे ठगी कर रहे हैं। बताया कि बीते कई दिनों से यहां आने वाले बेरोजगारों को मैं परेशान देख रहा था। इसकी जानकारी मैंने एएसपी विजय डाबर को दी। उनके निर्देश पर कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वहां काम करने वालों को अपने साथ थाना लेकर चली गई। ग्राम पिंडारा निवासी युवती ने बताया कि मुझसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर पांच सौ, ट्रेनिंग एवं रूम के लिए 2500 रुपए लिए हैं। चार दिन की ट्रेनिंग दिलवाई है। अब कह रहे हैं कि साक्षात्कार होगा। इसमें पास हुए तो काम मिलेगा। इसके लिए और पैसे लगेंगे। बताया कि ये लोग बताते है कि इनकी कंपनी छिंदवाड़ा व सिवनी में भी संचालित है। इसका मुख्यालय उदयपुर राजस्थान में है।

भोपाल में बस कुछ दिन और कम कीमत में मिल रही प्रॉपर्टी

भोपाल ■

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अफोर्डेबल प्राइज पर प्रॉपर्टी खरीदने का ये सबसे बेहतर समय है। क्योंकि, जल्द ही शहर में प्रॉपर्टी के दाम आसमान छूने वाले हैं। दरअसल, साल के इस फाइनेंशियल ईयर की शुरूआत यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली कलेक्टर की नई गाइडलाइन में 1283 लोकेशनों पर प्रॉपर्टी रेट्स औसतन 18 फीसदी की बढ़ोतरी प्रस्तावित है।

हालांकि, कहीं इसके दाम महज 5 फीसदी ही बढ़ेंगे तो कहीं इसमें 300 फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। भोपाल में होने जा रहे इस उतार चढ़ाव के चलते प्रॉपर्टी बाजार में भी हलचल मच गई है। क्रेडाई और अन्य रियल एस्टेट संस्थाओं ने इसे अनुचित बताते हुए विरोध किया है। हालांकि, केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड जल्द ही इसपर अंतिम फैसला लेगा।

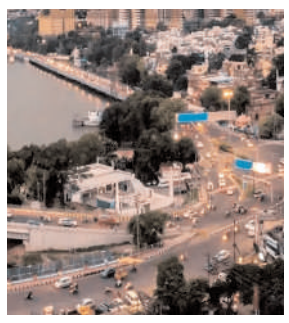

1283 लोकेशन्स पर औसत 18% होगी बढ़ोतरी

13 मार्च 2025 को भोपाल में उप मूल्यांकन समिति की बैठक में ये प्रस्ताव तैयार किया गया। इसमें भोपाल जिले की 2887 लोकेशनों में से 1283 पर प्रॉपर्टी रेट्स में 5% से लेकर 300% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। 2011-12 में 31.50 औसतन पॉपर्टी प्रतिशत बढ़ी थी। वहीं, इस बार औसतन 18 प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित है।

सेंट्रल इवेल्युएशन कमेटी को भेजा प्रस्ताव

13 मार्च को हुई उप मूल्यांकन समिति की बैठक के बाद ये प्रस्ताव अब केंद्रीय मूल्यांकन कमेटी को भेजा गया है। इस कमेटी की मंजूरी के बाद ही ये गाइडलाइन शहर की सभी लोकेशन्स पर लागू होगी। लेकिन 200 से ज्यादा आपत्तियों को देखते हुए संभावना है कि, इस बढ़ोतरी को आंशिक रूप से वापस भी लिया जा सकता है।

डिजिटल भारत में विचारों की बेड़ियां...

सरकार द्वारा ओटीटी प्लेटफार्मों की निगरानी, सोशल मीडिया पर टेकडाउन आदेश और आईटी नियम 2021 ने डिजिटल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया है। सेंसरशिप और आत्म-नियमन से प्लेटफार्म अधिक सामग्री हटाने लगे हैं, जिससे विचारों की विविधता प्रभावित होती है। झूठी सूचनाओं और साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुछ हद तक नियमन आवश्यक है।

-प्रियंका सौरभ
(लेखक)
ग्लोबल हेराल्ड

धारा 79 डिजिटल मंचों को मध्यस्थ सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन हालिया सरकारी हस्तक्षेप ने इस सुरक्षा को चुनौती दी है। सरकार द्वारा ओटीटी प्लेटफार्मों पर निगरानी, सोशल मीडिया पर टेकडाउन आदेश, और आईटी नियम 2021 का कड़ा अनुपालन डिजिटल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर रहा है। सेंसरशिप और आत्म-नियमन के भय से प्लेटफार्म अधिक सामग्री हटाने लगे हैं, जिससे विचारों की विविधता प्रभावित होती है। हालांकि, झूठी सूचनाओं और साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुछ हद तक नियमन आवश्यक है। इसीलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्लेटफार्म जवाबदेही के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। भारत को यूरोप के डिजिटल सर्विसेज एक्ट और अमेरिका के सेक्शन 230 जैसे संतुलित मॉडल से सीख लेकर, एक पारदर्शी और न्यायसंगत डिजिटल नीति अपनानी होगी। सूचना की इस नित परिवर्तनशील धारा में, जहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म विचारों के विस्तृत वितान की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं उन पर लगने वाली बंदिशें एक नवीन प्रश्नचिह्न उत्पन्न करती हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नियमन की कठोरता के मध्य झूलते इस युग में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) की धारा 79 एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि निर्मित करती है। आईटी अधिनियम की धारा 79 डिजिटल मंचों को एक ऐसा आश्रय प्रदान करती है, जो उन्हें उपयोगकताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री की जवाबदेही से मुक्त रखता है, बशर्ते कि: वे मात्र संदेश वाहक की भूमिका निभाएं, न कि नियंत्रक की। किसी अवैध सामग्री की सूचना मिलने पर, नियमानुसार उसे हटाने का यत्न करें। नवीनतम आईटी नियम, 2021 के प्रावधानों का अनुपालन करें। किन्तु, सरकार के हालिया कदमों ने इस कवच को किसी हद तक छिन्न-भिन्न करने का प्रयास किया है, जहाँ अभिव्यक्ति की आजादी और नियमन की शक्ति के मध्य एक सतत संघर्ष दृष्टिगोचर होता है।

सरकारी हस्तक्षेप: एक यथार्थपरक व्याख्या- सूचना और संप्रेषण के इस युग में सरकार द्वारा लागू किए गए कुछ प्रमुख हस्तक्षेपों पर यदि दृष्टिपात करें, तो पाते हैं कि ओटीटी प्लेटफार्मों पर बढ़ती निगरानी ने रचनात्मकता को एक कठोर परिधि में बाँधने का प्रयास किया है। सोशल मीडिया पर टेकडाउन आदेश विचारों के मुक्त प्रवाह में एक बाधा के समान प्रतीत होते हैं। आईटी नियम, 2021 का क्रियान्वयन डिजिटल संवाद के सहज प्रवाह को नियंत्रित करने की मंशा रखता है। कई

डिजिटल प्लेटफार्मों पर सामग्री प्रबंधन को लेकर पारदर्शिता की कमी उपयोगकताओं के अधिकारों पर प्रभाव डालती है। स्वतंत्र पत्रकारिता एवं वैकल्पिक दृष्टिकोणों को प्रतिबंधित करने की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर सकती है। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि सरकार द्वारा प्लेटफार्मों की स्वतंत्रता को सीमित करने और दायित्व को बढ़ाने की दिशा में एक अनवरत प्रयास किया जा रहा है।

विचारों की स्वतंत्रता बनाम उत्तरदायित्व का प्रश्न- सेंसरशिप और कंटेंट टेकडाउन जैसे कदम कलात्मक स्वतंत्रता, पत्रकारिता और राजनीतिक आलोचना पर गहरी छाया डालते हैं। आत्म-नियमन (स्व-नियमन) के भय से कई प्लेटफार्म स्वयं ही अधिक सामग्री हटाने लगते हैं, जिससे संवाद की विविधता प्रभावित होती है। सूचना तक पहुँच की स्वतंत्रता सीमित होने से नवाचार और बौद्धिक विमर्श बाधित होता है। डिजिटल मंचों पर झूठी सूचनाओं, घृणा व द्वेष फैलाने वाली सामग्री का उन्मूलन आवश्यक है।

उपयोगकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कुछ हद तक नियमन अपरिहार्य है। साइबर अपराध, ऑनलाइन उत्पीड़न और फेक न्यूज को रोकने के लिए प्लेटफार्मों को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। प्लेटफार्मों को समुदायिक मानकों और निष्पक्ष नीतियों का पालन करना चाहिए ताकि विचारों की अभिव्यक्ति को बाधित किए बिना एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाया जा सके।

संतुलन की आवश्यकता: मध्य मार्ग की खोज- किसी भी लोकतांत्रिक समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल प्लेटफार्मों की जिम्मेदारी के मध्य संतुलन आवश्यक होता है। इसके लिए: संविधान के अनुच्छेद 19(1)() के तहत अभिव्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हो। एक न्यायसंगत और पारदर्शी कंटेंट मॉडरेशन प्रणाली विकसित की जाए।ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों हेतु स्वतंत्र नियामक संस्था का गठन किया जाए। डिजिटल अधिकारों एवं दायित्वों की स्पष्ट व्याख्या हो। तकनीकी विशेषज्ञों, नागरिक समाज, और विधायकों के बीच निरंतर संवाद सुनिश्चित किया जाए। डिजिटल प्लेटफार्मों के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी अपील तंत्र विकसित किया जाए ताकि उपयोगकर्ता अपनी आपत्तियों को दर्ज कर सकें। कंटेंट मॉडरेशन और सेंसरशिप पर डेटा पारदर्शिता रिपोर्ट्स सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएं।

वैश्विक संदर्भ और भारत की स्थिति- यूरोपीय संघ का डिजिटल सर्विसेज एक्ट एक आदर्श उदाहरण है, जो ऑनलाइन प्लेटफार्मों के लिए संतुलित दायित्व निर्धारित करता है। अमेरिका में सेक्शन 230 प्लेटफार्मों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन प्रदान करता है। भारत को एक ऐसा ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है, जो न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करे बल्कि डिजिटल सुरक्षा और जवाबदेही को भी सुनिश्चित करे। सरकार, न्यायपालिका, और नागरिक समाज के सहयोग से एक प्रभावी डिजिटल नीति विकसित करना आवश्यक है। सूचना के इस महासागर में, जहाँ विचार लहरों की भांति गतिशील हैं, वहाँ नियमन और स्वतंत्रता के संतुलन की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। आईटी अधिनियम की धारा 79 डिजिटल प्लेटफार्मों को सुरक्षा प्रदान करती है, किन्तु हालिया सरकारी हस्तक्षेप यह दर्शाते हैं कि इस सुरक्षा कवच को सीमित किया जा रहा है। यदि सरकार एक समावेशी और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाए, तो भारत का डिजिटल परिदृश्य एक स्वतंत्र, सुरक्षित और न्यायसंगत दिशा में अग्रसर हो सकता है। डिजिटल भारत की शक्ति उसके नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति में ही निहित है। यदि सरकार, डिजिटल मंच और समाज मिलकर एक संतुलित रणनीति अपनाते हैं, तो यह तकनीकी युग लोकतंत्र की मूल भावना को सशक्त बना सकता है और भारत को वैश्विक डिजिटल क्रांति में अग्रणी बना सकता है। यदि सरकार, डिजिटल मंच और समाज मिलकर एक संतुलित रणनीति अपनाते हैं, तो भारत डिजिटल क्रांति में अग्रणी बन सकता है, जहाँ अभिव्यक्ति स्वतंत्र और सुरक्षित बनी रहेगी।

(नोट: इस लेख में ये दिए गए विचार लेखक के अपने विचार हैं)

सम्पादकीय

ढलती सांझें नारकीय जीवन जीने को मजबूर?

बुजुर्ग ढलती साझें है।ढलती साझें आज नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। वृद्धों को आश्रमों में भेजा जा रहा है।बुजुर्ग किसी दूसरे द्वारा नहीं बल्कि अपने ही बेटों के कारण उपेक्षित हैं शायद यह उनका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जिन बच्चों के लिए अपना पेट काटकर व भूखे रहकर उनका पालन पोषण किया आज वही बेटे उन्हे दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बुजुर्गों का तिरस्कार,एक खौफनाक त्रासदी है।आज देश में बुजुर्गों की जो हालत हो रही है उसके मामले समय-समय पर उजागर होते रहते है।कहते है बुजुर्ग अनुभवों की खान होते हैं।बुजुर्ग वटवृक्ष के सामान होते हैं जिनकी शीतल छाया में बच्चे सुरक्षित रहते है मगर आज अपने ही वृक्ष को काटने पर उतारु हो गए हैं। देश में आज लाखों वृद्ध लोग नारकीय जीवन जीने पर मजबूर हैं तथा दुसरों पर मोहताज हैं।बुजुर्गो ने पाई-पाई जोड़कर जिन बच्चों को मंहगी व उच्च तालिम देकर पैरों पर खडा.किया आज उन्ही के सामने दो जून की रोटी के लिए गिड़गडा रहे है।मां-बाप का कर्ज आज तक कोई नहीं चुका पाया है। बुजुर्गों ने अपनी खुशियों का गला घोंटकर अपने बच्चों को हर खुशी प्रदान की मगर आज वही चिराग माता -पिता के दुश्मन बन गए हैं बुजुर्ग परिवार का स्तम्भ होते हैं। आज देश में बुजुर्ग लोग तिरस्कृत जीवन जीने को मजबूर हैं। केन्द्र सरकार द्वारा वृद्धों के भरण-पोषण के लिए कानून बनाए हैं मगर वे फाईलो की धूल चाट रहे हैं नजीजन लोग कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आधुनिक युग की तथाकथित बहुएं व कलयुगी बेटे बुजुर्गों से बुरा व्यवहार कर रहे हैं।लेकिन एक दिन उन्हे भी बुढापा आयेगा तब उन्हें भी अपनी करनी का फल अवश्य मिलेगा। आज बुजुर्गो को स्टोर रुम में रखा जाता है मगर एक दिन स्टोर रुम तुम्हारा भी इंतजार कर रहा है जब तुम्हे भी ऐसा ही नसीब होगा।क्योकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अक्सर देखा गया है कि अधिकांश लोग वृद्ध आश्रमों की शरण ले रहे हैं क्योकि जब यह लोग दुखी हो जाते हैं तो वृद्ध आश्रम ही आखिरी विकल्प सूझता हैं। आज बहुत से वृद्ध एकाकी जीवन जी रहे ह। बेटों के पास आज समय नहीं हैं कि अपनों का सहारा बने हमें घर में अपने बुजुर्गों की दिन-रात सेवा करनी चाहिए क्योकिं बुजुर्गों की सेवा से बड़ा कोई तीर्थ नहीं हैं। आज स्थिति यह है कि वृद्ध लोग दाने-दाने को तरस रहे हैं।विडम्बना देखिए कि आज मां-बाप का बंटबारा किया जा रहा है उन्हे महिनों में बांटा गया है कि इस माह किस बेटे के पास खाना खाना है तथा अगले महिने दूसरे बेटे के घर खाना है।जिन मां बाप ने अपने बेटों में कभी भेदभाव तक नहीं किया आंच तक नहीं आने दी कांटा तक चुभने नहीं दिया आज वही बच्चे उनका बंटवारा कर रहे हैं।ऐसी परिस्थितियों के कारण कई लोग असमय ही मौत को गले लगा रहे हैं।बुजुर्गों के साथ बेंटो द्वारा मारपीट की घटनाएं भी होती रहती हैं।मारपीट के कारण कई मारे जा चुके हैं। ऐसी औलादें समाज पर कलंक है जो अपने ही जन्मदाताओं को नरक की जिन्दगी दे रहे है।लेकिन कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। समय बहुत बलवान होता है एक दिन सजा जरुर मिलेगी।गरीब लोग तो माता -पिता व बुजुर्गो की अच्छी सेवा करते है मगर साधन संपन्न लोगो द्वारा आज बुजुर्गो को ओल्ड ऐज होम तथा सरकार द्वारा बनाए गए वृद्ध आश्रमों में धकेला जा रहा है। आज वृद्धो को पुराना सामान समझ कर निकाला जा रहा हैं। लेकिन दुनिया में सब कुछ मिल जाता है मगर मां-बाप नहीं मिलते। बेचारे बुजुर्ग जिन पोते पोतियों को कंधों पर बिठाकर स्कूल से लाते थे और छोडते थे आज वही उनकी पिटाई तक करते हैं तथा उनका मजाक उडाते हैं। कुछ बुजुर्ग तो घर में ही कैद होकर रह गए हैं वे गुमनामी के अन्धेरे में जीने को मजबूर हैं। वृद्ध आज दयनीय स्थिति में जीवनयापन कर रहे हैं। सरकारों ने बुजुर्गों को पैशन की सुविधा दी है पर वह भी नाकाफी साबित हो रही है।सरकार को सख्ती से कानून लागू करने चाहिए ताकि वृद्धों को उनका हक मिल सके।सरकार व प्रशासन को ऐसे लोगों के विरुद्ध ठोस कारवाई करनी चाहिए तथा बुजुर्गों का अनादर करने वालो को दंडित किया जाए। दुनिया में सब कुछ मिल जाता है मगर मां-बाप एक ही बार मिलते है। जब तक बुजुर्गो को उनका सम्मान नहीं मिलेगा ऐसे वृद्ध दिवसों की कोई सार्थकता नहीं होगी।

नरेन्द्र भारती
लेखक
ग्लोबल हेराल्ड

संविधान के नाम पर कांग्रेस का दोहरा रवैया दुर्भाग्यपूर्ण

-ललित गर्ग- | लेखक

कांग्रेस एक बार फिर संविधान को लेकर विवादों से घिर गयी है। संविधान के संबंध में कांग्रेस का दोहरा रवैया एवं चरित्र एक बार फिर देश के सामने आया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर हाथ में संविधान की प्रति लेकर भाजपा पर इसे बदलने का आरोप लगाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय अपनी हर सभा में इस आरोप को दोहराते रहे कि अगर भाजपा फिर से सत्ता में आई तो संविधान बदल कर आरक्षण खत्म कर देगी, इसका भाजपा को नुकसान भी उठाना पड़ा है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भाजपा पर संविधान बदलने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस आज खुद संविधान बदलने की बात कर रही हैं। दरअसल, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ओबीसी कोटा के तहत पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण देने जा रही है, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों में मुसलमानों को 4 प्रतिशत आरक्षण के संदर्भ में जब उप- मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार को यह याद दिलाया गया कि संविधान के तहत मजहब के आधार पर आरक्षण देना मुमकिन नहीं है, तब उन्होंने इशारा किया कि आरक्षण देने के लिए जरूरी बदलाव किए जाएंगे। शिवकुमार के इस बयान के बाद कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक फिर संविधान बचाने का सियासी अभियान हावी हो गया है। इस बार भाजपा आक्रामक है और उसने फिलहाल इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। इस वर्ष बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का यह अहम मुद्दा बन जाये तो कोई आश्चर्य नहीं है।

ग्लोबल हेराल्ड

मुस्लिम तुष्टिकरण के लिये कांग्रेस सरकारें अपने-अपने राज्यों में अतिश्योक्तिपूर्ण घोषणाएं एवं योजनाएं लागू करती रही हैं, कर्नाटक में भी वहां के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने सरकार का बजट पेश करते हुए मुस्लिमों के लिए कई घोषणाएं की। सीएम ने एलान किया कि सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों में से 4 प्रतिशत अब श्रेणी-बी के तहत मुसलमानों के लिए आरक्षित होंगे। सरकार ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों के लिए 15 महिला कॉलेज खोले जाएंगे। इसका निर्माण वक्फ बोर्ड की ही जमीन पर किया जाएगा, लेकिन सरकार इस पर पैसा खर्च करेगी। मौलवियों को 6000 मासिक भत्ता देने की भी व्यवस्था इस बजट में की गई है। कर्नाटक सरकार के बजट में दलितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए समुचित बजट आवंटित नहीं हुआ लेकिन मुस्लिम तुष्टिकरण के चलते मुस्लिमों के लिये लुभावना बजट आवंटित किया गया है। जबकि सरकारों का काम किसी धर्म एवं समुदाय विशेष का तुष्टिकरण न होकर सभी समुदायों का पुष्टीकरण होना चाहिए। जब संविधान में धर्म आधारित आरक्षण का निषेध किया गया है तो फिर जानबूझकर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा इसे सूचीबद्ध करके विधि सम्मत क्यों बनाया जा रहा है?

दरअसल, भाजपा और कांग्रेस, दोनों देश की प्रमुख पार्टियों को यह एहसास हो चला है कि संविधान इस देश में बहुत संवेदनशील विषय है और इस पर लोग कतई समझौता नहीं करेंगे। संविधान केवल न्यायिक या वैधानिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि वह भारत की जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस अर्थ में यह देश के जन-जन के मन का दस्तावेज है। संविधान भारत में सभी नागरिकों के लिए दिग्दर्शक तत्व है। इसलिए, प्रश्न यह उठता है कि जब संविधान इतना स्पष्ट है तो क्या संविधान की मूल भावना पर केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए आघात करना स्वस्थ लोकतंत्र का लक्षण है? दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पवित्र ग्रंथ पर भी विपक्षी दल एवं कांग्रेस अत्यंत निकृष्ट राजनीति करती जा रही है। जो कांग्रेस शासन में रहते हुए कभी संविधान का सम्मान नहीं कर सकी, वह आज विपक्ष में बैठकर यह भ्रम फैलाने में लगी है कि मोदी सरकार संविधान को खत्म कर देगी। सच तो यह है कि कांग्रेस जैसे दल आज अपने मूल राजनीतिक विचार को खो बैठे हैं। कांग्रेस अपने गांधीवादी विचार और समाजवादी पार्टी जैसे दल समाजवाद और राम मनोहर लोहिया के मूलभूत विचारों को भूल चुके हैं। संविधान को आधार बनाकर विपक्षी दल जनता को विभाजित करने, मुस्लिम तुष्टिकरण एवं राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेंकने बाज नहीं आ रहे हैं। आश्चर्य नहीं, कांग्रेस ने संविधान को लेकर जो हथियार चलाया था, वही हथियार कर्नाटक में स्वयं कांग्रेस के विरुद्ध चला गया है। अब इससे होने वाले नुकसान का भान होते ही कांग्रेस तत्काल बचाव में लग गई। वैसे, शिवकुमार के स्पष्टीकरण के बावजूद भाजपा इस मुद्दे पर निशाना साध रही है, तो संकेत साफ है, वह सियासत का मौका जाने नहीं देना चाहेगी। वह संविधान बदलने और न बदलने पर फिर से गर्म हुई राजनीति को ठंडा नहीं होने देगी। बीते लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा निशाने पर थी, वहीं इस बार कांग्रेस निशाने पर आ गई है। लोकसभा-राज्यसभा में एवं इस वर्ष बिहार में होने वाले चुनावों में भाजपा कांग्रेस पर आक्रामक रहेगी। अब तो तीर कमान से निकल चुका है, भले ही अब कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री शिवकुमार सफाई देने में लगे हैं कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया और वह संविधान में बदलाव का प्रस्ताव कभी नहीं रखेंगे। स्पष्ट है कि हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण का पक्षधर नहीं है। डॉ. भीमराव आंबेडकर भी ऐसे आरक्षण के हिमायती नहीं थे। संविधान सभा में एकमत के साथ यह तय हुआ था कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब अगर ऐसे आरक्षण की जरूरत पड़ने लगी है, या कांग्रेस मुसलमानों के वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिये आरक्षण का हथियार चलाती है तो संविधान में संशोधन तो करना ही होगा। अपने आजाद देश में जरूरतमंदों को आरक्षण देने के लिए करीब 12 बार संविधान में संशोधन किए गए है और मुस्लिमों को महज मजहबी बुनियाद पर आरक्षण देने के लिए भी ऐसी जरूरत पड़ेगी। गांधी परिवार के अत्यंत करीबी कर्नाटक के डिप्टी सीएम के बयान को सुनकर लोग हैरत में हैं। लोग संविधान के खिलाफ धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कांग्रेस की कोशिश का विरोध कर रहे हैं। धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में संविधान की धज्जियां उड़ा दी है।ह्न कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण के लिये देश को दांव पर लगाती रही है। एक बार फिर उसकी इस कोशिश से उसका असली चेहरा देश के सामने आया है। कांग्रेस भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, मुस्लिम आरक्षण को संविधान में जगह देकर संविधान निमार्ता बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफत की जा रही है। मुस्लिमों को आरक्षण असंवैधानिक हैं। कांग्रेस बार-बार मुस्लिम आरक्षण की वकालत कर संविधान की मूल भावना को चुनौती दे रही है। मुस्लिम वोटबैंक के लिए ऐसा किया जाना संविधान की मूल भावना से खिलवाड है। राहुल गांधी एवं कांग्रेस पार्टी का रवैया आरक्षण को लेकर समय-समय पर बदलता रहा है। कभी उसने संविधान संशोधन की बात की, तो कभी आरक्षण का विरोध किया, तो कभी धर्म के आधार पर आरक्षण देने के प्रयास भी किए। आपातकाल के काले दौर में कांग्रेस द्वारा ऐसा भी किया गया, जब इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान की मूल प्रस्तावना ही बदल डाली। कांग्रेस नेता संविधान की किताब जेब में रखते हैं, लेकिन इसे कमजोर करने के लिए हरसंभव कोशिश भी करते हैं। अब कांग्रेस अध्यक्ष को पार्टी की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और देश को बताना चाहिए कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव क्यों करना चाहती है? कांग्रेस का रवैया हर प्रकार से संविधान विरोधी ही रहा है। संविधान को कमजोर करने वाले अनेक प्रयास कांग्रेस समय-समय पर करती आई है। कांग्रेस द्वारा अपने शासनकाल में इस पर संशोधन लाने का प्रयास किया गया कि सरकार संविधान में क्या-क्या परिवर्तन कर सकती है? स्पष्ट है कि कांग्रेस के लिए हमारा संविधान केवल सत्ता को साधने का एक उपकरण मात्र रहा है, संविधान के प्रति सम्मान की भावना कांग्रेस के चरित्र में नहीं है। जबकि वर्ष 2014 में सत्तारूढ़ होने के बाद से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार संविधान के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। भारतीय संविधान और लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की मंशा से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं।

भड़कने से कुछ नहीं होता-कोर्ट कार्यवाही करे

इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने हाल ही में फैसला दिया था। जिसमें कहा गया था, लड़की के स्तनों को पकड़ना, उसके पजामे की डोरी तोड़ना और रेप की कोशिश करना रेप नहीं माना जा सकता है। गंभीर धाराओं में मुकदमा चलाये जाने को आपत्तिजनक मानते हुए साधारण धाराओं में मामला चलाने का आदेश हाईकोर्ट के जज ने दिया था। पुलिस ने पाकसो के तहत रेप का मामला दर्ज किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले की देश भर में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। वूमेन ऑफ इंडिया नाम के एक संगठन ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वयं संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उक्त आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के जिस न्यायमूर्ति द्वारा यह आदेश लिखाया गया था, उन्हें फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट के जज वीआर गवई तथा जस्टिस आगस्टीन जार्ज मसीह की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए जज महोदय को कड़ी फटकार लगाई है। पिछले कुछ वर्षों से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज प्रकरणों की सुनवाई करने के दौरान जिस तरह की टिप्पणियां करते हैं। उसके कारण देश की न्यायिक व्यवस्था को लेकर लोगों के मन में संदेह उठने लगा है। निष्पक्षता और राजनीतिक सरोकार को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जो मामले सुनवाई के लिए उनके पास पहुंचते हैं, उन पर सुनवाई करने और फैसला देने के स्थान पर आधी अधूरी टिप्पणी करके मामले को लंबित रखा जाता है। पिछले एक दशक में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सैकड़ों फैसलों की समीक्षा की जाए, तो यह प्रमाणित होगा। जिस मामले के लिए याचिका लगाई गई थी, उस मामले का निराकरण आज तक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी और आदेश जारी किए हैं, वह सभी आधे-अधूरे हैं। जिसके कारण न्याय जगत में अराजकता फैल गई है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षक हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व न्यायपालिका के पास है। संविधान ने न्यायपालिका को सर्वोच्चता पर रखा है। जो न्याय त्वरित रूप से हो सकता है, उसको लंबे समय तक टालकर रखने से न्यायपालिका की उपयोगिता आम आदमी के लिए खत्म होती जा रही है। न्यायालय में कई वर्षों तक मामलों में तारीख पर तारीख मिलती रहती है। एक मामले में तो देखते ही देखते महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार अवैध रूप से गिरा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के बाद भी 4 साल बाद भी निर्णय नहीं आ पाया। इससे न्यायपालिका की असलियत उजागर होती है। संवेदनशील मामलों में भी न्यायपालिका ने स्वयं संज्ञान लेकर सुनवाई करने के दरवाजों को पूरी तरह से बंद कर लिया है। पिछले एक दशक में न्यायपालिका की जो छवि आम लोगों के बीच में बन रही, उसके मुताबिक न्यायपालिका सरकार के इशारे पर काम कर रही है। सरकार की इच्छा के विपरीत न्यायपालिका से कोई निर्णय नहीं होता। लगभग 70 फीसदी मामलों में जो लोग न्यायालय न्याय पाने के लिए पहुंचते हैं। वह केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और जिला प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई के खिलाफ न्यायालय में जाते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में न्यायपालिका से आम आदमियों और विपक्षी राजनीतिक दलों को कोई राहत नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश से जो बुलडोजर का कानून सरकार ने शुरू किया था, बिना किसी नियम कानून के लोगों के घर तोड़ दिए गए। सारे परिवार को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया गया। परिवार रोटी-रोजी के लिए मोहताज हो गया। न्यायपालिका यह दृश्य पिछले कई वर्षों से खुली आंखों से देख रही है। जान रही है, समय-समय पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आदेश भी जारी कर रही है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को सरकारें मानने के लिए तैयार नहीं है। कार्यपालिका के अधिकारियों के ऊपर भी न्यायपालिका का कोई दबाव नहीं रह गया है। न्याय पालिका के जजों में शायद वह नैतिकता नहीं रह गई है, जो सरकार के खिलाफ आदेश दे सकें। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कई बार सुप्रीम कोर्ट और सार्वजनिक मंचों से यह बात कह चुके हैं। सरकार न्यायाधीशों का डोजियर तैयार करती है। उसके बाद उनके ऊपर मनमाने फैसले के लिए दबाव बनाती है। कई बार तो सीधे-सीधे यह तक कह दिया गया है कि सरकार जजों को ब्लैकमेल कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह के निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, उसको देखते हुए अब यह भ्रम नहीं सत्य प्रतीत हो रहा है। न्यायपालिका सरकार के दबाव में काम कर रही है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के दूसरे नंबर के वरिष्ठ जज के घर में आग लगी। उनके घर में करोड़ों रुपए की नगदी जल गई। इसको लेकर भी न्यायपालिका के ऊपर एक अलग संकट देखने को मिल रहा है। सरकार के लिए न्यायाधीश की यह आपदा में एक अवसर बन गई है। सरकार कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने की दिशा में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। पिछले एक दशक से कॉलेजियम की क्या हालत है। यह किसी से छिपी नहीं है। सरकार उन्ही जजों की नियुक्ति, प्रमोशन और ट्रांसफर करती है। जो सरकार के अनुकूल होते हैं। कॉलेजियम की अधिकांश अनुशंसा सरकार नहीं मानती है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक ही विचारधारा के जजों को नियुक्त किए जाने के आरोप भी लग रहे हैं। कॉलेजियम की जो अनुशंसा सरकार को अच्छी नहीं लगती है। उन फाइलों को केंद्र सरकार अपने पास रोककर बैठ जाती है। न्यायपालिका के वह निर्णय जो सरकार के अनुकूल नहीं होते हैं, उन्हें सरकार ठंडे बस्ते में डाल देती है, या कानून बनाकर उन निर्णयों पर अमल नहीं होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय पारित करके भूल जाती है। बुलडोजर के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा जो मनमानी पिछले कई वर्षों से की जा रही है, उसके खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई आदेश जारी कर चुके हैं।

सनत जैन
लेखक
ग्लोबल हेराल्ड

(नोटः इस लेख में ये दिए गए विचार लेखक के अपने विचार हैं)

हर जीव में व्याप्त नारायण

वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम-पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले है। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों में विद्यमान हैं। यद्यपि वे बहुत दूर हैं, फिर भी हमारे निकट हैं- आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतरू हम भौतिक इन्द्रियों से न तो उन्हें देख पाते हैं, न समझ पाते हैं अतएव वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इन्द्रियां असमर्थ हैं।

किन्तु जिसने, भक्ति में कृष्णभावनामृत का अभ्यास करते हुए, अपने मन-इन्द्रियों को शुद्ध कर लिया है, वह उन्हें निरन्तर देख सकता है। ब्रघ्संहिता के अनुसार परमेर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है, वह निरन्तर उनके दर्शन कर सकता है। और भगवद्गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा देखा-समझा जा सकता है। भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बंटे हुए हैं? नहीं। वास्तव में वे एक हैं। जैसे सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई पांच हजार मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहां है, तो सभी कहेंगे कि वह उसके सिर पर चमक रहा है। इस उदाहरण का अर्थ है कि यद्यपि भगवान अविभाजित हैं, लेकिन इस प्रकार स्थित हैं मानो विभाजित होंवैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान हैं। जिस तरह एक सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है। यद्यपि परमेर प्रत्येक जीव के पालनकर्ता हैं, किन्तु प्रलय के समय सबका भक्षण भी कर जाते हैं। सृष्टि रची जाती है, तो वे सबको मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय सबको निगल जाते हैं। वैदिक शास्त्र पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा आश्रय-स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती हैं और प्रलय बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं।

ग्लोबल हेराल्ड में प्रकाशित होने वाले लेख लेखकों के निजी विचार है

व्यापार

शेयर बाजार बढ़त पर बंद

मुंबई ■

भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को बढ़त पर बंद हुआ। बाजार में ये तेजी एशियाई बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बाद भी खरीदारी हावी रहने से आई है। अमेरिका के वाहन आयात पर नए टैरिफ की घोषणा से वैश्विक बाजारों में आई कमजोरी के बाद भी घरेलू बाजार में बढ़त रही। वित्तीय स्टॉक में आये उछाल से आज बाजार ऊपर आये। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स अंत में 317.93 अंक करीब 0.41 फीसदी ऊपर आकर 77,606.43 अंक पर बंद हुआ।

वहीं इसी प्रकार 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ़्टी भी अंत में 105.10 अंक तकरीबन 0.45 फीसदी की बढ़त के के साथ्ज्ञ ही 23,591.95 पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान सेंसेक्स की कंपनियों में बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी, इंडसइंड बैंक, लार्सन एंड टुब्रो और बजाज फाइनेंस के शेयर सबसे अधिक लाभ में रहे। इनमें 2.85 फीसदी तक की तेजी रही। वहीं टाटा मोटर्स, सन फार्मा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटक महिंद्रा बैंक और भारती एयरटेल के शेयर नीचे आये। इसमें 5.38 फीसदी तक की गिरावट रही। 13 प्रमुख क्षेत्रो में से ग्यारह में बढ़त रही। स्मॉल-कैप और मिड-कैप में 1.2 फीसदी और 0.4 फीसदी की वृद्धि हुई। वहीं, निफ्टी ऑटो और फार्मा को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुए। अमेरिका के अप्रैल से ऑटो आयात पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद से ही वाहन शेयरों में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी ऑटो इंडेक्स गुरुवार को 1.04 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ।

सोने-चांदी में तेजी

नई दिल्ली। घरेलू बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई है। इनके वायदा कारोबार की शुरूआत में भी तेजी रही है। दोनों कीमती धातुओं में तेजी के साथ कारोबार शुरू हुआ। एक समय पर सोने के वायदा भाव 88,000 रुपये जबकि चांदी के भाव 99,750 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार में भ सोने-चांदी के वायदा भावों में तेजी रही। सोने के वायदा भाव की शुरूआत तेजी के साथ हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएस) पर सोने का बेंचमार्क अप्रैल अनुबंध आज 147 रुपये बढ़कर 87,785 रुपये के भाव पर खुला। वहीं इसका पिछला बंद भाव 87,638 रुपये था। ये 88,156 रुपये के भाव पर दिन के उच्च और 87,785 रुपये के भाव पर दिन के निचले स्तर पर पहुंचा। सोने के वायदा भाव पिछले सप्ताह 89,796 रुपये के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचे थे। वहीं चांदी के वायदा भाव की शुरूआत तेज रही।

सैमसंग से सरकार ने मांगे 5154 करोड़ रुपए

नई दिल्ली ■

केंद्र सरकार ने सैमसंग व उसके अधिकारियों से 60.1 करोड़ डॉलर (करीब 5,154 करोड़ रुपये) मांगे हैं। सैमसंग पर आरोप है कि उसने देश में प्रमुख दूरसंचार उपकरणों के आयात पर टैरिफ से बचने के लिए हेराफेरी की थी। यह मांग भारत में सैमसंग के पिछले साल के 95.5 करोड़ डॉलर के मुनाफे का बड़ा हिस्सा है। कंपनी नेटवर्क विभाग के जरिये दूरसंचार उपकरणों का आयात करती है।

कंपनी को मोबाइल टावरों में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन कलपुर्जे पर 10 या 20 फीसदी के टैरिफ से बचने के लिए आयात को गलत तरीके से वगीर्कृत करने पर 2023 में चेतावनी दी गई थी। सैमसंग ने कलपुर्जों का आयात कर जियो को बेचा। सैमसंग की जांच 2021 में तब शुरू हुई जब कर निरीक्षकों ने मुंबई व गुरुग्राम में कार्यालयों की तलाशी में दस्तावेज, ईमेल व उपकरण जब्त किए। सीमा शुल्क आयुक्त ने आदेश में कहा, सैमसंग ने कानूनों का उल्लंघन किया है और सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। लाभ बढ़ाने के लिए सैमसंग ने सरकारी खजाने को चूना लगाया। कंपनी ने व्यावसायिक नैतिकताओं और उद्योग मानकों का उल्लंघन किया। सैमसंग विवाद रिमोट रेडियो हेड के आयात पर केंद्रित है। यह एक रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट है जो छोटे आउटडोर मॉड्यूल में संलग्न होता है।

एअर इंडिया ने कर्मचारियों के लिए बनाई नई यात्रा नीति

मुंबई। भारतीय विमानन कंपनी एअर इंडिया ने अपनी कर्मचारियों के लिए एक नई यात्रा नीति का ऐलान किया है, जिसके तहत कंपनी के सीईओ, शीर्ष अधिकारी और वरिष्ठ कमांडर इकोनॉमी क्लास में यात्रा करेंगे। यह नीति अगले महीने से चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। इस नीति के अनुसार, शीर्ष प्रबंधन के लिए यह विवरण 1 अप्रैल से लागू होगा, जबकि वरिष्ठ कमांडरों के लिए यह 1 जून से प्रभावशाली होगी। एअर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि इस नीति का मकसद है कंपनी की प्रीमियम सीटें उपलब्ध रखना ताकि ग्राहकों को सुविधा मिले। नई एअर इंडिया की इस सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि ग्राहकों के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण अवसर है जो कंपनी की प्रगतिशील सोच और ग्राहक-केंद्रित संस्कृति को दशार्ती है। इसके साथ ही नीति में अपग्रेड विकल्प भी शामिल है जो ग्राहकों को बेहतर सुविधा प्रदान करता है।

वित्तीय समावेश में अनपेक्षित बाधाओं से सावधानी की जरूरत: आरबीआई गवर्नर

मुंबई ■

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को कहा कि विनियमनों से वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने में अनपेक्षित बाधाएं उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के यहां आयोजित कार्यक्रम में मल्होत्रा ने कहा कि नीति निमार्ताओं को भी सावधान रहना चाहिए और अपने उपायों को लेकर अति उत्साही नहीं होना चाहिए। मल्होत्रा ने कहा कि भारत ने वित्तीय समावेश की दिशा में पर्याप्त प्रगति की है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विनियमन वित्तीय समावेश में अनपेक्षित बाधाएं उत्पन्न न करें। हमें उचित संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते समय ग्राहकों के अधिकारों और सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। गवर्नर ने कहा, जबकि हम अपनी वित्तीय प्रणालियों को धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ सुरक्षित बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें नीति निमार्ताओं के रूप में यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारे उपाय अति उत्साही न हों और वैध गतिविधियों तथा निवेशों को बाधित न करें। गवर्नर ने संतुलित विनियमन की वकालत करते हुए कहा कि जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाना लाभकारी होगा तथा लोगों व व्यवसायों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना आवश्यक है।

Alfa Valley
India

बास्केटबॉल चैंपियनशिपः बालिका वर्ग में मेरठ की टीम जीती, बालक में ट्रिपल टीएसी का ट्रॉफी पर कब्जा

बरेली ■

ये रहे अतिथि- मुख्य अतिथि एसएसपी अनुराग आर्य, विशिष्ट अतिथि एसपी साउथ अशिका वर्मा, कुलाधिपति फ्यूचर यूनिवर्सिटी मुकेश गुप्ता, अध्यक्ष मानस स्थली ट्रस्ट सत्येंद्र प्रकाश गोयल, सचिव मानस स्थली ट्रस्ट सौरभ अग्रवाल, प्रधानाचार्य मानस स्थली रेसिडेंशियल स्कूल अनिल कुमार त्रिपाठी, सीओ सिटी पंकज श्रीवास्तव, यूपीबीए उपाध्यक्ष आरएस बेदी, संयुक्त सचिव यूपीबीए पवन कुमार, परमवीर सिंह उपस्थित रहे।

बरेली के फरीदपुर स्थित मानस स्थली आवासीय विद्यालय में चल रही 23वीं यूथ यूपी राज्य बास्केटबॉल चैंपियनशिप के अंतिम दिन सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले गए। इस मौके पर प्रतियोगिता में प्रदेश की 43 टीमों के 600 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। फाइनल में बालिका वर्ग में मेरठ, बालक वर्ग में ट्रिपल टीएसी ने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।

बालिका वर्ग में मेरठ ने बुलंदशहर को 85-68 से पराजित कर विजेता का खिताब अपने नाम किया। सेमीफाइनल मुकाबले में बुलंदशहर ने लखनऊ को 52-27 से तथा मेरठ ने गौतम बुद्ध नगर को 44-37 से मात देकर फाइनल में प्रवेश किया था। तीसरे स्थान के लिए हुई भिड़ंत में लखनऊ ने गौतम बुद्ध नगर को 20-00 से पराजित किया। बालक वर्ग में ट्रिपल टीएसी ने मेरठ को 62-48 से मात देकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। सेमीफाइनल में मेरठ ने गोरखपुर को 40-23 से और ट्रिपल टीएसी ने गौतम बुद्ध नगर को 46-18 से पराजित कर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया था। तृतीय स्थान के लिए गौतम बुद्ध नगर और गोरखपुर के बीच मुकाबला हुआ। इसमें गौतम बुद्ध नगर ने गोरखपुर को पराजित कर तीसरा स्थान हासिल किया।

आइटा टेनिस चैंपियनशिप

आशी को हराकर सिद्धि बनीं एकल चैंपियन, बालक एकल फाइनल में अनिरुद्ध से भिड़ेंगे सानिध्य

लखनऊ ■

लखनऊ की खिलाड़ी सिद्धि सिंह ने आदर्श भसीन मेमोरियल अंडर-18 आइटा टेनिस चैंपियनशिप में बालिका एकल खिताब अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में यूपी की आशी शमशेरी को कड़े मुकाबले में 7-6(7-4), 3-6, 7-5 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। प्रतियोगिता के पुरुष एकल फाइनल में शीर्ष वरीय सानिध्य धर द्विवेदी का सामना सातवीं वरीयता प्राप्त अनिरुद्ध कुमार से होगा। अनिरुद्ध पहले ही बालक युगल फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं।

उत्तर प्रदेश टेनिस एसोसिएशन के तत्वावधान में एसडीएस अकादमी की ओर से विजयंत खंड स्टेडियम के टेनिस कोर्ट पर आयोजित टूर्नामेंट में बालिका एकल के फाइनल में उत्तर प्रदेश की सिद्धि सिंह ने उत्तर प्रदेश की ही आशी शमसेरी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला। करीब चार घंटे तक चले मैराथन मुकाबले में सिद्धि सिंह ने पहला सेट कड़े संघर्ष के बाद टाईब्रेक में 7-6 (7-4) से जीता। दूसरे सेट में आशी ने रणनीति में बदलाव करते हुए 6-3 से जीत दर्ज की। तीसरे सेट में एक-एक अंक के लिए हुए करीबी संघर्ष में सिद्धि ने उम्दा स्ट्रोक व दमदार फोरहैंड शॉट का सहारा लिया और 7-5 से जीत हासिल की।

मनोरंजन

पैसेंजर्स की परवाह करने का दावा करने वाली एयरलाइन में हमदर्दी कहां है: लीजा रे

हाल ही में मशहूर अभिनेत्री लीजा रे ने एक एयरलाइन पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस मामले ने तूल पकड़ लिया। एक पोस्ट साझा करते हुए लीजा रे ने बताया कि उनके 92 वर्षीय बीमार पिता की हालत के चलते उन्हें अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी, लेकिन डॉक्टर का प्रमाणपत्र जमा करने के बावजूद एयरलाइन ने किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने लिखा, फिर से शुरू हो गया। मेरे पिता 92 साल के हैं और बीमार हैं। मुझे उनकी बीमारी के कारण ट्रैवल कैंसिल करना पड़ा। डॉक्टर का लेटर सबमिट करने के बाद भी छूट देने से इंकार कर दिया गया? ये कैसे संभव है? पैसेंजर्स की परवाह करने का दावा करने वाली एयरलाइन में हमदर्दी कहां है? उनकी इस पोस्ट के वायरल होते ही लोगों ने एयरलाइन की नीति और रवैये की आलोचना करनी शुरू कर दी। बढ़ते विवाद को देखते हुए एयरलाइन ने भी जवाब दिया और लीजा रे से उनके ईमेल आईडी या केस आईडी की जानकारी मांगी ताकि वे इस मामले की समीक्षा कर सकें। एयरलाइन ने कहा, डियर लीजा रे, हम आपकी चिंता से हमदर्दी रखते हैं और आपके पिता के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं।

जैमी लीवर अब अमेरिका में अपनी कॉमेडी से दर्शकों को करेगी लोटपोट

भारत के बाद अब अमेरिका में मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर की बेटी जैमी लीवर अपनी कॉमेडी से दर्शकों को लोटपोट करने जा रही हैं। जैमी लीवर ने अपने उत्तरी अमेरिका टूर 'द जैमी लीवर शो' की घोषणा की और इसे प्रमोट करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एडिटेड वीडियो मजेदार अंदाज में शेयर किया। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जैमी ने यह वीडियो पोस्ट किया, जिसमें ट्रंप के भाषणों के कुछ अंश एडिट किए गए हैं और जैमी अपनी अनोखी हाजिरजवाबी से इसका जवाब देती नजर आ रही हैं। वीडियो की शुरुआत में ट्रंप पूछते हैं, आप कहां से हैं? इस पर जैमी करीना कपूर के स्टाइल में कहती हैं, प्लीज, आपको नहीं पता मैं कहां से हूं? जहां से सुनीता विलियम्स हैं, मैं भी वहीं से हूं। वीडियो में आगे ट्रंप कहते हैं, क्या आप थोड़ा तेज बोल सकती हैं? इस पर जैमी फिर करीना के पूजा अवतार में जवाब देती हैं, ड्रामा ना करो, वो कौन है, जिसने मुझे मुड़कर नहीं देखा? इस एडिटेड बातचीत में जब ट्रंप कहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कह रही हैं, तो जैमी कंगना रनौत के अंदाज में बोलती हैं, देखिए, भारत एक खूबसूरत देश है और अमेरिका प्रेरणा है। कभी-कभी हममें प्रेरणा की कमी होती है, लेकिन मैं वादा करती हूं कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करने में मदद करूंगी। बातचीत के अंत में ट्रंप कहते हैं, शुभकामनाएं और शांति से रहें, जिस पर जैमी तुरंत जवाब देती हैं, लेकिन ट्रंप जी, हम आपको शांति में नहीं रहने देंगे!

जल्द हो सकता है 'गजनी 2' का ऐलान, आमिर और मुरुगादॉस में बातचीत जारी

खबर है की गजनी-2 का ऐलान जल्द हो सकता है क्योंकि साउथ के जाने-माने निर्देशक एआर मुरुगादॉस और बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। चर्चा है कि दोनों 'गजनी 2' पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही इस पर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। यह फिल्म हिंदी और तमिल दोनों भाषाओं में बनाई जाएगी, जिसमें आमिर खान और तमिल स्टार सूर्या अपनी-अपनी भूमिकाएं दोहराते नजर आ सकते हैं। हालांकि, एआर मुरुगादॉस ने इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि इस पर चर्चा जारी है। हाल ही में अपने एक साक्षात्कार में मुरुगादॉस ने कहा कि वह और आमिर खान इस प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल दोनों अपने-अपने प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं। जैसे ही सही समय आएगा, वे इस पर आगे चर्चा करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि वह हाल ही में मुंबई आए थे, जहां उन्होंने सलमान खान के साथ अपनी आगामी फिल्म 'सिकंदर' की शूटिंग शुरू की और उसी दौरान आमिर खान से भी मुलाकात की। गौरतलब है कि 2008 में रिलीज हुई 'गजनी' बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म बनी थी, जिसने 100 करोड़ रुपये की कमाई का रिकॉर्ड बनाया था। फिल्म में आमिर खान के साथ असिन लीड रोल में थीं, और इसे दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। यह फिल्म 2005 में आई तमिल फिल्म 'गजनी' की हिंदी रीमेक थी, जिसमें सूर्या मुख्य भूमिका में थे। अब अगर 'गजनी 2' बनती है, तो यह न केवल आमिर खान के करियर के लिए एक महत्वपूर्ण फिल्म होगी, बल्कि इंडियन सिनेमा के लिए भी एक बड़ा प्रोजेक्ट साबित हो सकती है।

पीएसएल में करांची किंग्स की कप्तानी करते हुए नजर आयेंगे वॉर्नर

लाहौर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डेविड वॉर्नर अगले माह 11 अप्रैल से शुरु हो रहे पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के 10 सत्र में करांची किंग्स की कप्तानी करते हुए नजर आयेंगे। कराची किंग्स ने वॉर्नर को अपना नया कप्तान बनाया है। वार्नर को शान मसूद की जगह कप्तान बनाया गया है। वॉर्नर पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हुए नजर आएंगे। वॉर्नर को इससे पहले आईपीएल में किसी भी टीम ने अपने साथ नहीं जोड़ा था। ऐसे में उन्होने पीएसएल में खेलने पाक का रुख किया। वॉर्नर को इसमें कराची ने उन्हें अपने साथ जोड़ा। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल ने वॉर्नर को कप्तान सौंपने पर खुशी जताते हुए कहा, हम डेविड वॉर्नर का नए कप्तान के रूप में कराची किंग्स परिवार में स्वागत करते हैं।

जिम्बाब्वे में ट्राई सीरीज खेलेंगे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, दोनों टीमें 2-2 टेस्ट भी खेलेंगी

नई दिल्ली ■

जिम्बाब्वे क्रिकेट के एमडी बोले- देश में तेजी से बढ़ेगा क्रिकेट

जिम्बाब्वे क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर गिवमोर मैकोनी ने होम सीजन पर कहा, टेस्ट और टी-20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की मेजबानी करना जिम्बाब्वे में क्रिकेट के विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। हम दोनों टीमों के स्वागत के लिए तैयार है, देश के क्रिकेट फैंस भी सीरीज के लिए एक्साइटेड हैं।

साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड इस साल जिम्बाब्वे में टी-20 फॉर्मेट की ट्राई सीरीज खेलेंगे। दोनों टीमें जिम्बाब्वे के खिलाफ 2-2 टेस्ट भी खेलने वाली हैं। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने अपने होम सीजन का शेड्यूल रिलीज किया। तीनों टीमें 28 जून से 11 अगस्त तक 4 टेस्ट और 7 टी-20 खेलेंगी।

साउथ अफ्रीका टीम जिम्बाब्वे में 2014 के बाद पहली बार कोई टेस्ट खेलेगी। 28 जून से 10 जुलाई तक दोनों के बीच बुलवायो में 2 टेस्ट होंगे। 14 जुलाई से हरारे में ट्राई सीरीज शुरू होगी। जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के बीच ही पहला मैच खेला जाएगा। न्यूजीलैंड 16 जुलाई को दौरे पर पहला टी-20 खेलेगी। ट्राई सीरीज का फाइनल 26 जुलाई को हरारे में ही होगा। जिम्बाब्वे में 2018 के बाद पहली बार कोई ट्राई सीरीज होगी। 7 साल पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने यहां 3 टीमों की टी-20 सीरीज खेली थी। 30 जुलाई से 11 अगस्त तक कीवी टीम बुलवायो में होम टीम के खिलाफ 2 टेस्ट खेलेगी।

निडर होकर खेल रहे युवा भारतीय क्रिकेटरों से प्रभावित हैं स्टोइनिस

नई दिल्ली ■

आईपीएल में पंजाब किंग्स की तरफ से खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने भारत के युवा क्रिकेटरों की जमकर प्रशंसा की है। स्टोइनिस ने कहा कि जिस प्रकार से भारतीय युवा खिलाड़ी निडर होकर खेल रहे हैं वह सराहनीय है। स्टोइनिस के अनुसार इसी कारण भारतीय टीम को टी20 प्रारुप से रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के एकसाथ संन्यास लेने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इनकी जिम्मेदारी बाद तिलक वर्मा , अभिषेक शर्मा और वाशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ियों ने अच्छी तरह से संभाल ली है। वह पंजाब किंग्स के युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्य की पारी से भी प्रभावित नजर आये। स्टोइनिस ने कहा, 'भारतीय क्रिकेट में काफी गहराई है। वह हमेशा से रही है। और मेरा मानना है कि आईपीएल से उनके खिलाड़ियों को विश्व स्तर पर अपने कौशल का नमूना पेश करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा, ' युवा खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरे हैं क्योंकि उन्हें अपने करियर की में ही आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में दबाव के हालातों से गुजरने का लाभ मिल जाता है। खेल के प्रति उनका आक्रामक रवैया वास्तव में शानदार है।

इंग्लैंड दौरे पर भी रोहित ही रहेंगे कप्तान : रिपोर्ट

मुम्बई ■

रोहित शर्मा का आगामी इंग्लैंड दौरें में भी भारतीय टीम का कप्तान बने रहना तय है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) इस दौरे के लिए कप्तानी में किसी प्रकार के बदलाव के पक्ष में नहीं है। भारतीय टीम साल 2007 के बाद पहली बार इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने के इरादे से इस दौरे पर जाएगी।

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की ये सीरीज 20 जून से हेडिंग्ले में शुरू होगी। इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम विफल रही थी। जिसके बाद से ही माना जा रहा था कि रोहित को कप्तानी से हटाया जा सकता है पर चैम्पियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम को मिली जीत के बाद बोर्ड रोहित को अभी और अवसर देना चाहता है। रोहित ने भी हाल ही में कहा था कि अभी उनका संन्यास का कोई इरादा नहीं है। चयन समिति के आईपीएल फाइनल से पहले इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम घोषित करने की उम्मीद है। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर वाली समिति इसके साथ ही चार दिवसीय मैचों के लिए इंडिया ए टीम का भी चयन करेगी। ये मैच टेस्ट सीरीज से पहले खेले जाएंगे। इस टीम में राष्ट्रीय टीम के कुछ खिलाड़ी भी खेलेंगे। रोहित के खराब फार्म के कारण पिछले दिनों उन्हें टीम में जगह दिये पर भी सवाल उठे थे। उन्होंने सितंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच 10 टेस्ट मैचों में केवल 164 रन बनाए थे।

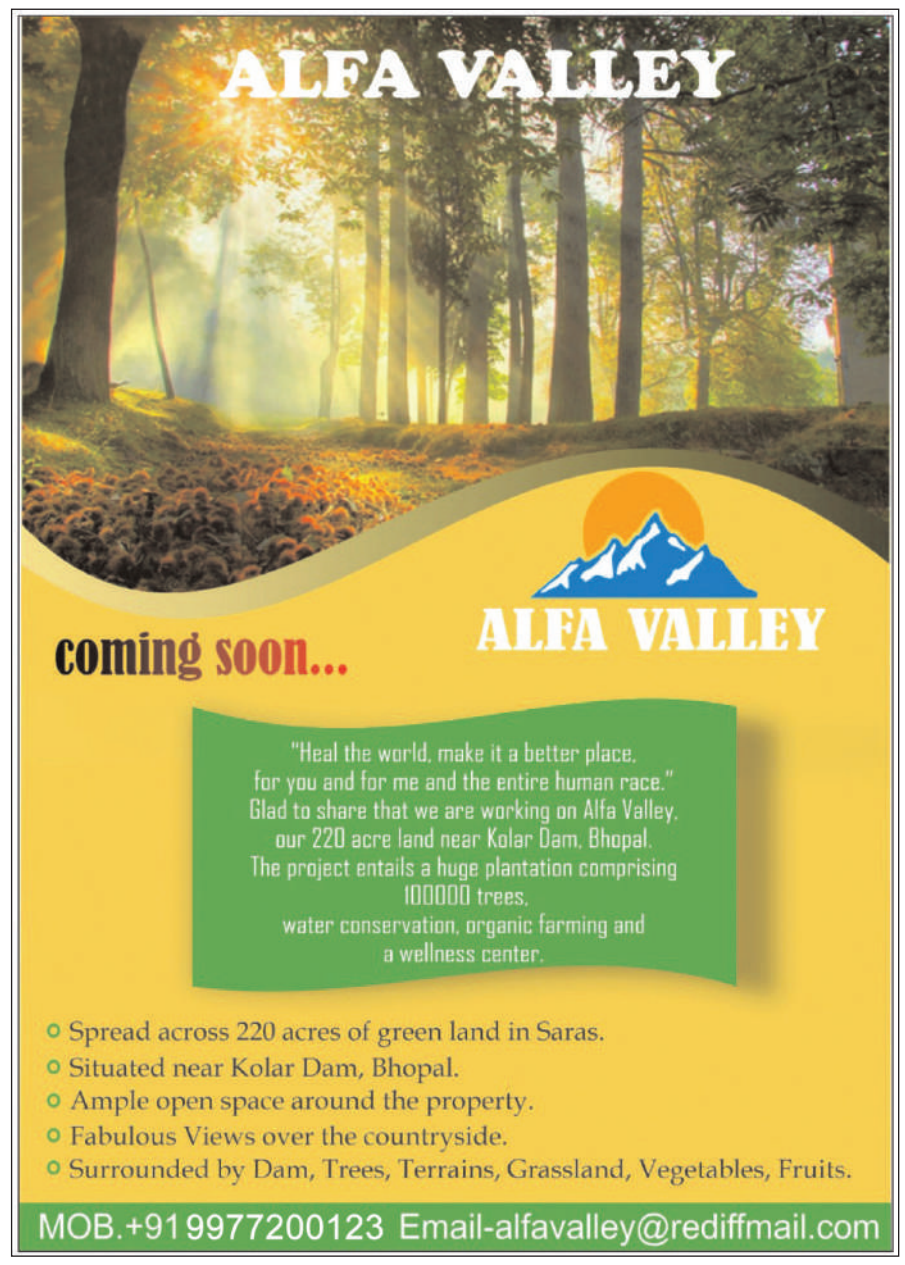

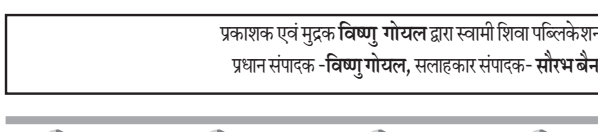

प्रकाशक एवं मुद्रक **विष्णु गोयल** द्वारा स्वामी शिवा पब्लिकेशन के लिए 1-ए, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स एबी रोड, इंदौर, मध्यप्रदेश से प्रकाशित एवं पी.जी. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रा.लि. रिलायंस पेट्रोल पम्प के पीछे, सेंटर पाइंट, मांगलिया बायपास, इंदौर, मध्यप्रदेश से मुद्रित। Epaper_www.globalherald.news

प्रधान संपादक -**विष्णु गोयल**, सलाहकार संपादक- **सौरभ बैनर्जी**, प्रदेश संपादक- **दिलीप शर्मा**, स्थानीय संपादक **सत्येन्द्र जैन** *(*समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार)। मोबाइल नं.:-7999509078, आर.एन.आई. नं. MPHIN/2012/41876, email- editor@nationalherald.org/globalheraldeditor@gmail.com